शर्मा हार्डओवेर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 278 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 15 मई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर ब्रिक्स देशों की एकजुटता महत्वपूर्ण : भारत पेज 2
नागा और कुकी समुदायों के 38 से अधिक लोगों को विभिन्न समूहों ने बंधक बना रखा पेज 3
पेपर लीक आरोपियों का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं : राठौड़ पेज 5
एस्टन विला के खिलाफ मोहम्मद सलाह की वापसी तय, कुछ मिनट ही खेल पाएंगे... पेज 7

door graphy Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती है और इसी से आपके जिंदगी का महत्व निर्माण होता है।

- जोशहुआ जे मरीन

असम सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा, चार को मिली अहम जिम्मेदारी

26 के बाद होगा कैबिनेट विस्तार

गुवाहाटी। असम में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आज अपने मंत्रिमंडल के चार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर विभागों की सूची जारी की गई। फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार तक कई अहम विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा के साथ शपथ लेने वाले चार मंत्रियों में भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता न्योग, एजीपी के अतुल बोरा और बीपीएफ के चरण बोरो शामिल हैं। इन चारों नेताओं को अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश्वर तेली को श्रम कल्याण, चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण व ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहीं अजंता न्योग को महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग सौंपा गया है। असम गण परिषद के नेता अतुल बोरा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, असम समझौता क्रियान्वयन, सीमा संरक्षण एवं विकास और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। दूसरी ओर, चरण बोरो ने पिछली सरकार की तरह इस बार भी परिवहन और बोड़ोलैंड कल्याण विभाग अपने पास बरकरार रखा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय के विस्तार तक बाकी सभी विभाग मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के पास रहेंगे। शर्मा ने बुधवार को संकेत दिया था कि विधानसभा के पहले सत्र के 26 मई को समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजनीतिक तौर पर भी इन नियुक्तियों को संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है। रमेश्वर तेली चाय जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अजंता नेओग महिला चेहरा हैं, अतुल बोरा -शेष पृष्ठ दो पर

क्राइम ब्रांच में पवन खेड़ा से दूसरे दिन भी हुई लंबी पूछताछ, 25 को वापस बुलाया

गुवाहाटी (हि.स.)। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा गुरुवार को लगातार दूसरे दिन असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुए। यह पूछताछ असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़े कथित बहु-विदेशी पासपोर्ट मामले को लेकर चल रही जांच के संबंध में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को पवन खेड़ा से

करीब 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई। हालांकि, क्राइम ब्रांच कार्यालय में प्रवेश करते समय और बाहर निकलने के बाद मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह अब भी अपने पुराने आरोपों और बयानों पर कायम हैं, तब भी उन्होंने चुप्पी बनाए रखी। जानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को आगे की पूछताछ -शेष पृष्ठ दो पर

असम का पेड़ा स्वादिष्ट है : सीएम

गुवाहाटी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़े पासपोर्ट मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पेश हुए। खेड़ा के पूछताछ के लिए पहुंचने पर, मुख्यमंत्री शर्मा ने कामाख्या मंदिर में पूजा करते हुए पत्रकारों से कहा कि असम के पेड़े का स्वाद अच्छा है, -शेष पृष्ठ दो पर

दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी वाहनों के ईंधन की खपत 20 फीसदी कम करने और *मेरा भारत मेरा योगदान* अभियान जैसी कई घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के मद्देनजर दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में इससे संबंधित फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईंधन संकट और बढ़ती आयात लागत का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में देशहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्एक नागरिक का -शेष पृष्ठ दो पर

जल्द ही फिर से शुरू होगी सीमा वार्ता : सीएम

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. सांग्मा ने आश्वासन दिया है कि असम के साथ अनसुलझे सीमा विवादों पर बातचीत जल्द ही फिर से शुरू होगी। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नव निर्वाचित असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्यभार संभालने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। असम में नई सरकार ने अभी-अभी शपथ ली है, इसलिए कुछ दिन बीतने दीजिए। मैं असम के मुख्यमंत्री से बात करूंगा और हम जल्द ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सांग्मा ने कहा। दोनों देशों द्वारा अपनी -शेष पृष्ठ दो पर

कानूनी बाधाएं दूर होने से कामाख्या कॉरिडोर के काम में तेजी आएगी : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा कि गुवाहाटी में महत्वाकांक्षी मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना पर काम आने वाले दिनों में तेज हो जाएगा क्योंकि पुनर्विकास पहल से जुड़ी अधिकांश कानूनी बाधाएं अब हल हो गई हैं। एक्स से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और नीलाचल पहाड़ी पर स्थित पूजनीय कामाख्या मंदिर के दर्शन करने वाले

तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मैंने मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकांश कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, आने वाले दिनों में काम में तेजी आएगी। हमारा लक्ष्य मां कामाख्या मंदिर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को एक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करना है, शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। फरवरी 2024 में शुरू की गई 498 करोड़ -शेष पृष्ठ दो पर

मेघालय में 30 हजार विस्फोटक जब्त, असम के दो व्यक्ति गिरफ्तार

शिलांग। मेघालय पुलिस ने पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में उमकियांग में नाका चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से 30,000 विस्फोटक डेटोनेटर जब्त किए और दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुरुवार की रात करीब 2:30 बजे उमकियांग गांव के 2 किलो इलाके में पंजीकरण संख्या एएस-10ए-5916 वाली एक सफेद हैचबैक कार को रोका, जबकि वाहन कथित तौर पर असम के सिलचर की ओर जा रहा था। तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस ने दो गत्ते के डिब्बों और एक बोरी में छिपाए गए 30,000 विस्फोटक डेटोनेटर बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि इन विस्फोटकों का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान जमालपुर के कमरुल अली लस्कर और लोकनाथपुर के इब्राहिम उद्दीन लस्कर के रूप में की गई, दोनों असम के कछार जिले के रहने वाले थे। लुमशनॉन्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। विस्फोटकों के स्रोत और इच्छित गंतव्य का पता -शेष पृष्ठ दो पर

पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट

गुवाहाटी (हि.स.)। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट-एक्ट फर्स्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर राज्यों का विकास जिस तेजी से हो रहा है। इससे आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत विकसित भारत के विकास का इंजन बन सकेगा। पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहे जाने वाले गुवाहाटी शहर के विकास से न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि आसियान देशों के लिए भी व्यापार के दरवाजे गुवाहाटी से खुल जाएंगे। ऐसे महत्व वाले शहर गुवाहाटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट।

करीब 5,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली महत्वाकांक्षी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना को पूर्वोत्तर भारत की सड़क संपर्क व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। इस परियोजना से गुवाहाटी शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) टोल मॉडल के तहत दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इंफोकोन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे गए इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 121 किलोमीटर होगी। परियोजना के प्रमुख हिस्सों में बाइहाटा चारियाली से सोनापुर तक -शेष पृष्ठ दो पर

ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हमला, भारत ने जताई कड़ी नाराजगी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने इस घटना को *अस्वीकार्य* बताते हुए समुद्री व्यापार और नागरिक नाविकों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रनधीर जायसवाल ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और निर्दोष नागरिक चालक दल को निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला अस्वीकार्य है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि -शेष पृष्ठ दो पर

चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की

नई दिल्ली (हि.स.)। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने से जुड़ी प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का निर्देश जारी कर दिया है। एसआईआर के पहले दो चरणों में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल थे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश कवर होगा। आंध्र प्रदेश (4,16,16,061), अरुणाचल

प्रदेश (8,87,607), चंडीगढ़ (5,18,663), दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (4,27,849), हरियाणा (2,06,63,155), झारखंड (2,64,89,777 मतदाता), कर्नाटक (5,55,74,064), महाराष्ट्र (9,86,64,413), मणिपुर (20,91,999), मेघालय (23,43,252), मिजोरम (8,75,004), नागालैंड (13,56,858), दिल्ली (1,48,23,234), ओडिशा (3,34,33,659), पंजाब (2,14,56,297), -शेष पृष्ठ दो पर

चीनी के एक्सपोर्ट पर भारत सरकार की सितंबर तक रोक

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार महंगाई में बढ़ोतरी को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए चीनी के निर्यात पर अगले 30 सितंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाणिज्य विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है जो तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। चीनी के चालू सीजन (अक्तूबर-सितंबर) में चीनी का उत्पादन 280 लाख टन से कम करने का अनुमान -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में कांगपोकपी घटना के बाद कुकी-जो इलाके में भारी तनाव

इंफाल (हि.स.)। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में घात लगाकर किए गए हमले में चर्च से जुड़े तीन लोगों की मौत एवं चार लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुकी-जो बहुल इलाके में भारी विरोध जारी है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को आधिकारिक बयान में बताया कि 13 मई को कांगपोकपी जिले के न्यू कीथेलमानबी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत साहिबुंग गांव के पास से गुजर रहे दो वाहनों पर अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा बिना किसी उकसावे के की गई गोलीबारी में, तीन नागरिकों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। इस अपराध में शामिल लोगों को

पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने आस-पास के इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना को लेकर प्रभावित इलाके -शेष पृष्ठ दो पर

एचसी पहुंचीं ममता के खिलाफ लगे चोर के नारे, हुई धक्का-मुक्की

कोलकाता। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट परिसर में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा।

चुनाव बाद हुई कथित हिंसा से संबंधित एक मामले में पैरवी करने पहुंची ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थीं, तब वकीलों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ *चोर-चोर* के नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नारेबाजी के दौरान कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच ममता ने वकीलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन लोगों ने मुझे मारा है। अदालत में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल कोई *बुलडोजर स्टेट* नहीं है और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि -शेष पृष्ठ दो पर

तालिबान ने दिया भारत को अफगान-पाक बॉर्डर का ठेका

नई दिल्ली। जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भाई होने का ढोंग छोड़कर अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच 46 मिलियन डॉलर यानी करीब 400 करोड़ की एक ऐसी ऐतिहासिक डील हुई है जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पाकिस्तान की दादागिरी का अंत है। आखिर अचानक भारत ने तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ इतनी बड़ी इतनी भयानक डील क्यों की जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर

बंद करके बैठा है। झड़पें हो रही हैं और अफगान परिवार भूखे प्यासे परेशान है। तब भारत ने 6 मिलियन लगाकर यह कदम क्यों उठाया? पाकिस्तान ने तोरखम और स्पिन बोल्डक जैसे प्रमुख रास्तों को पूरी तरह से बंद कर रखा है। हजारों ट्रक सड़कों पर सड़ रहे हैं और अफगान किसानों के अंगूर, अनाज और सब्जियां मिट्टी में मिल रही है। पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान की सेना सीमा पर गोलीबारी कर रही है। मासूम अफगान परिवारों को जबरन उनके घरों से निकाल रही है और मासूम बच्चे दाने-दाने को मोहताज हैं। अब पाकिस्तान जो नापाक देश है उसका मकसद साफ है अफगानिस्तान को भूखा मारो उसे इतना कमजोर कर दो कि वो घुटने पर आ जाए। इतना ही नहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी डब्ल्यूएफपी चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि -शेष पृष्ठ दो पर

पश्चिम बंगाल : सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य

कोलकाता। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 18 मई से वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि निजी विद्यालयों से भी इसे अपनाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में औपचारिक सूचना आज बाद में जारी की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि

सोमवार से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। निजी स्कूलों में भी इसे शामिल करने की अपील की गई है। इस संबंध में आज औपचारिक नोटिस जारी किया जाएगा। एक अलग घटनाक्रम में, अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर ब्रिक्स देशों की एकजुटता महत्वपूर्ण : भारत

नई दिल्ली (हि.स.)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों से वैश्विक संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता और व्यापारिक व्यवधानों से निपटने के लिए *व्यावहारिक तालमेल* विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों की एकजुटता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया अभूतपूर्व भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इसके अलावा वैश्विक व्यवस्था में शक्ति संतुलन और लोकतांत्रिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया भी जारी है, जिसे सभी देश सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों का असर ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पर पड़ा है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, बढ़ती महंगाई और आर्थिक वृद्धि की सीमित संभावनाओं ने विकासशील देशों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला और विविधीकृत बाजारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वैश्विक संकटों के प्रभाव को कम किया जा सके। केवल चर्चा पर्याप्त नहीं है, बल्कि ब्रिक्स देशों को समन्वित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा के मुद्दे आज भी वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। उन्होंने हाल के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और अधिक रेखांकित किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद होना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि गाजा संघर्ष के गंभीर मानवीय परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने स्थायी युद्धविराम, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में विश्वसनीय प्रयासों की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। जयशंकर ने कहा कि लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

आसनसोल के कोयला खदान में एयर ब्लास्ट, 40 से ज्यादा श्रमिक घायल

कोलकाता (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) के कुनुस्तोरिया क्षेत्र स्थित पड़ाशिया (परशिया) कोलियरी की भूमिगत खदान में हुए भयावह एयर ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 40 से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि एक श्रमिक की मौत हो गई है। हालांकि, खदान प्रबंधन की ओर से खबर लिखे जाने तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह पहली शिफ्ट के दौरान करीब 10:30 बजे खदान के 27 नंबर विभाग में श्रमिक कोयला कटाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खदान की एक परत से तेज एयर ब्लास्ट हुआ, जिससे भीतर जबरदस्त वायु दबाव बन गया। विस्फोट से श्रमिक दूर जा गिरे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय उक्त खदान में करीब 20-25 कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें दो अधिकारी भी शामिल थे। बता दें कि, खदान में एयर ब्लास्ट एक अत्यंत खतरनाक घटना है, जो मुख्य रूप से भूमिगत कोयला खदानों में छत गिरने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें खदान की खाली जगह में फंसी हवा अचानक भारी दबाव के साथ बाहर निकलती है, जो खनिकों को घायल या मृत कर सकती है और मशीनरी को तबाह कर सकती है। प्रत्यक्षदर्शी श्रमिक राकेश कुर्मी ने बताया कि करीब 10:30 बजे अचानक जोरदार धमाका महसूस हुआ। देखते ही देखते तेज हवा का दबाव बना और वहां मौजूद सभी लोग गिर पड़े। कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पूरा क्षेत्र धूल और धुएं से भर गया। उस समय करीब 20-25 लोग वहां काम कर रहे थे, जिनमें दो अधिकारी भी थे। हादसे से खदान के अंदर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पाकर मौजूद अधिकारियों और बचाव दल ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर रानीगंज के बांसड़ा एरिया अस्पताल, ईसीएल के अन्य अस्पतालों तथा दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, कई घायलों की हालत गंभीर है। घायलों में कई ठेका मजदूरों के साथ-साथ कोलियरी के अतिरिक्त प्रबंधक दिलीप कुमार भी घायल हुए हैं। इस घटना के बाद खदान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इधर, हादसे के विरोध में श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

फाजिल्का बॉर्डर पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन

चंडीगढ़ (हिंस)। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशा और हथियार तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन सीमा पार से ड्रोन गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार देर रात फाजिल्का के भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार गांव चक्क बाजीदा के खेतों में ड्रोन गिरने की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान खेतों से एक ड्रोन बरामद किया गया। इस मामले में थाना सदर जलालाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चौकी घुबाया के इंचार्ज गुरनाम सिंह ने बताया कि बीएसएफ से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। उन्होंने बताया कि एक किसान के खेत में गेहूं के नाड़ के बीच ड्रोन पड़ा मिला, जिसे कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मेयर ने पेयजल की किल्लत पर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

सोनीपत (हिंस)। सोनीपत मेयर चुनाव लगातार दूसरी बार जीतने के बाद राजीव जैन अगले ही दिन एक्शन मोड में दिखाई दिए। गुरुवार को उन्होंने पार्षदों के साथ शहर के वाटर बूस्टिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान कालूपुर चुंगी के पास बने नए बूस्टिंग स्टेशन से कई महीनों बाद भी पानी की सप्लाई शुरू न होने पर मेयर ने फोन पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सभी बूस्टिंग स्टेशनों का तुरंत निरीक्षण किया जाए और दो दिनों के भीतर कमियों को दूर कर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। पार्षदों से भी अपने-अपने वार्ड के बूस्टिंग स्टेशनों पर नजर रखने को कहा गया। मेयर पार्षद संजय ठेकेदार और राजकुमार शर्मा के साथ कालूपुर के नए बूस्टिंग स्टेशन पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला। अधिकारियों ने बताया कि यहां लगी दोनों मोटर पच्चीस हॉर्स पावर क्षमता की हैं, जो दबाव से पानी नहीं उठा पा रही हैं। इस पर मेयर ने तुरंत चालीस हॉर्स पावर की मोटर लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुरथल गांव स्थित पम्प हाउस का निरीक्षण किया गया। यहां सात में से केवल दो ट्यूबवेल चालू मिले।

NO.GDBG-144/AW&DC-17/2024-25/ *Dated Gossaigaon the 14th March/2026*

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender are invited in F-2 Form for the works shown below from the intending Registered Contractor of Class-I and Class-II (A, B & C) category of Assam PWD (Roads & Building) with affixing Non-refundable court fee of Rs.8.25 (Rupees Eight and paise twenty five) only in a prescribed Form under **(AW&DC)** fund for the year 2025-26. The Tender will be received on **08-06-2026** upto 1:00 PM in the Office of the undersigned and will be opened on same day at 1:30 PM in the Office of the undersigned and C.S. will be submitted to the B.D.O ,Gossaigaon Development Block , Gossaigaon for approval.

Sl. No.	Name of work	Estimated amount	Bid Security	Cost of BID documents (D/D) @ 0.03% (Approx.)	Time of completion
1	Const. of Village road with earth filling and Sand gravelling from Mohan Bihar PWSS to Durga Mandir under VCDC, Babubil	Rs. 10,00,000.00	Rs. 10,000/- @ 1% for ST/SC/OBC & Rs. 20,000/- @ 2% for General	Rs. 300/-	3 (Three) Months from the date of issue of work order.

The Terms and Condition details may be seen at Notice Board in the Office of the Block Development Officer, Gossaigaon Development Block, Gossaigaon from **14-05-2026 to 08-06-2026** up to 1:00 PM.

Sd/-
Block Development Officer,
Gossaigaon Dev. Block, Gossaigaon

IPR(BTC)/C/2026-27/155

पृष्ठ एक का शेष

असम सरकार में हुआ ...

क्षेत्रीय असमिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि चरण बोरो बोड़ो आदिवासी समुदाय से आते हैं। गौरतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने हालिया विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 102 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। हिमंत विश्व शर्मा ने 12 मई को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

क्राइम ब्रांच में पवन...

के लिए 25 मई को फिर से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले बुधवार को भी उनसे लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिसके बाद देर रात उन्हें जाने की अनुमति दी गई थी। बुधवार की पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उल्लेखनीय है कि, यह मामला गुवाहाटी में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। इसके बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोपों को झूठा और मानहानिकारक बताया था। बाद में पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया। उच्चतम न्यायालय ने पहले उन्हें गौहाटी उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की, जिसके बाद से वह जांच एजेंसियों के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित हो रहे हैं।

असम का पेड़ा...

इस टिप्पणी को व्यापक रूप से कांग्रेस नेता पर कटाक्ष के रूप में देखा गया। मंदिर में बोलते हुए, शर्मा ने असम के भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि महामाया मां कामाख्या के आशीर्वाद से, हमारा राज्य अगले पांच वर्षों में आगे बढ़ेगा। पुलिस स्टेशन के बाहर, खेरा ने पत्रकारों से कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और मैं इसमें सहयोग कर रहा हूं। यह विवाद अप्रैल में खेरा द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है, जब उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास भारत, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं, और दुबई में उनकी कुछ अघोषित आलीशान संपत्तियां हैं, साथ ही अमेरिका के व्योमिंग में पंजीकृत एक कंपनी भी है। शर्मा परिवार ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए इन दस्तावेजों को पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा प्रसारित *एआई-जनित मनगढ़ंत कहानियां* बताया है।

मेघालय में 30 हजार ...

लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों को संदेह है कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल क्षेत्र में अवैध कोयला खनन गतिविधियों में किया जाना था। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक पदार्थों की खरीद, भंडारण और उपयोग से संबंधित अनुमतियां जिला स्तर पर जारी की जाती हैं, जबकि पुलिस उनके संचालन और परिवहन से जुड़े कानून और व्यवस्था पहलुओं की निगरानी करती है। सूत्रों ने आगे दावा किया कि विस्फोटकों की दस्तावेजी मात्रा और जमीन पर उनके वास्तविक उपयोग के बीच अक्सर विसंगतियां सामने आती हैं।

पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी...

55.54 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड नॉर्दर्न बाइपास का निर्माण शामिल है। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में ब्रह्मपुत्र नद पर कुरुआ से नारेंगी के बीच प्रस्तावित छह लेन का पुल भी शामिल है। लगभग तीन किलोमीटर लंबे इस पुल से मालवाहक और यात्री वाहनों की आवाजाही तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इससे गुवाहाटी शहर के भीतर मौजूदा मार्गों पर यातायात का दबाव भी कम होगा। बाइपास और पुल निर्माण के अलावा एनएच-27 के कुछ हिस्सों को चौड़ा करने की योजना भी बनाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से सिलचर, शिलांग और अपर असम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक संपर्क बेहतर होगा तथा व्यापार, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। वन भूमि हस्तांतरण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पहले ही प्रदान की जा चुकी है। हालांकि, हाथी गलियारों (एलिफेंट कॉरिडोर) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई शर्तें भी लगाई गई हैं। वन्यजीवों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए वशिष्ठ और जोराबाट के बीच एलिवेटेड रोड सेक्शन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 के मानसून के बाद निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि परियोजना को चरणबद्ध तरीके से 2027 से 2030 के बीच पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 वर्ष की कंसेशन अवधि वाले इस मॉडल में चार वर्ष निर्माण के लिए निर्धारित किए गए हैं।

चुनाव आयोग ने 16 ...

सिक्किम (4,71,094), त्रिपुरा (28,97,674), तेलंगाना (3,39,20,705) और उत्तराखंड (79,76,466) शामिल हैं। मतदाता सूची अपडेट करने के दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से मिलेंगे। इसमें उनकी सहायता 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) करेंगे। बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से गणना चरण के दौरान नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे प्रतएक मतदान केंद्र के लिए बीएलए नियुक्त करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक संदेश में कहा कि मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपने गणना फॉर्म भरें। आयोजन का उद्देश्य मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं को ही शामिल करना और अपात्र व्यक्ति का हटाना है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर के लिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली (ड्राफ्ट रोल) 5 जुलाई को प्रकाशित होगी, जबकि अंतिम निर्वाचक नामावली 6 सितंबर को जारी की जाएगी। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए ड्राफ्ट रोल 10 जुलाई और अंतिम रोल 11 सितंबर को प्रकाशित होगा। उत्तराखंड के लिए ड्राफ्ट रोल 14 जुलाई और अंतिम रोल 15 सितंबर को जारी होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित होगी, जबकि अंतिम नामावली 22 सितंबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना और पंजाब के लिए ड्राफ्ट रोल 31 जुलाई और अंतिम रोल 01 अक्तूबर को प्रकाशित होगा। कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के लिए ड्राफ्ट रोल 5 अगस्त को और अंतिम रोल 7 अक्तूबर को जारी होगा। नागालैंड के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली 20 सितंबर और अंतिम नामावली 22 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। त्रिपुरा के लिए ड्राफ्ट रोल 21 अक्तूबर को प्रकाशित होगा, जबकि अंतिम निर्वाचक नामावली 23 दिसंबर को जारी की जाएगी।

चीनी के एक्सपोर्ट पर ...

है जबकि घरेलू स्तर पर चीनी की खपत 280 लाख टन से अधिक की है। चीनी की कीमत में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए ही चीनी के निर्यात पर सितंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। अप्रैल की खुदरा महंगाई दर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले तीन प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी रही। वहीं गुरुवार को जारी थोक महंगाई दर आठ प्रतिशत से ऊपर चली गई है। चीनी का सीजन एक अक्तूबर से शुरू होता है। चीनी के स्टाक की कमी रहने पर जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान चीनी की कीमत अधिक बढ़ती है। अक्तूबर से चीनी मिल उत्पादन शुरू कर देती है जिससे बाजार में नई चीनी की आवक शुरू हो जाती है। इस साल मानसून पर अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है। बारिश की कमी से गन्ने के उत्पादन में कमी होने पर चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। चीनी मिलर्स का कहना है कि इस साल अक्तूबर में चीनी सीजन के आरंभ होने के समय 40-45 लाख टन चीनी का स्टाक रहेगा जबकि यह स्टाक 70-80 लाख टन तक का होता है। वर्ष 2022-23 में भी सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत की तरफ से चीनी के निर्यात पर रोक लगाने से वैश्विक स्तर पर भी चीनी के दाम बढ़ेंगे। ब्राजील के साथ भारत चीनी का बड़ा निर्यातक देश हैं।

मणिपुर में कांगपोकपी ...

में भारी विरोध एवं नाराजगी देखी जा रही है। कुकी-जो से जुड़े सबसे बड़े धार्मिक संगठन कुकी इनपी, मणिपुर ने चर्च से जुड़े लोगों पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे *शांति पर ही हमला* किए जाने की बात कही है। कांगपोकपी में कुकी-जो चर्च से जुड़े लोगों की हत्या के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुकी संगठनों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि, मणिपुर के कांगपोकपी में, घात लगाकर मारे गए लोगों के शव लेने के लिए हजारों लोग बीती रात जिला अस्पताल के बाहर जमा हो गए। पूरी रात लोग अस्पताल के बाहर एकत्र होकर प्रार्थना करते नजर आए। हत्या के विरोध में कुकी इनपी, मणिपुर ने कुकी-जो बहुल इलाकों में 48 घंटे के बंद का ऐलान किया है। घटना की जानकारी मिलते ही मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह बुधवार शाम शिजा अस्पताल पहुंचकर कांगपोकपी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की और इस हमले की निंदा की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं, मणिपुर की उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने कहा है कि तीन लोगों पर किया गया यह बर्बर हमला किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, उन्होंने कांगपोकपी में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा की है। थाडौ चर्च से जुड़े लोगों पर हुए क्रूर हमले के बाद मणिपुर के विधायकों ने न्याय की मांग की और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की।

ओमान तट के पास ...

व्यापारिक जहाजों और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं। भारत ने बचाव अभियान चलाने के लिए ओमान की सरकार और अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। बयान में कहा गया कि सभी भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं और हम उनके बचाव के लिए ओमानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और समुद्री व्यापार को बाधित करना टाला जाना चाहिए। इससे पहले ब्रिटेन के समुद्री सुरक्षा संगठन यूकेएमटीओ ने खाड़ी क्षेत्र में एक गंभीर समुद्री सुरक्षा घटना की जानकारी दी थी। यूकेएमटीओ के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तट से लगभग 38 नॉटिकल मील दूर एक जहाज पर *अनधिकृत लोगों* ने कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज लंगर डाले हुए था और बाद में उसे ईरानी जलक्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा था। यह घटना ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और यहां किसी भी तरह की अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और तेल आपूर्ति मार्गों पर खतरा बढ़ रहा है। यूकेएमटीओ ने क्षेत्र में मौजूद जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी है।

एचसी पहुंचीं ममता ...

राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मामलों को नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सभी घटनाएं चुनाव के बाद नहीं हुए है। इसके साथ ही सभी मामलों में आरोपितों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। मालूम हो कि गुरुवार सुबह मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की पीठ के समक्ष चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े एक जनहित मामले की सुनवाई थी। वकील शीर्षान्य बनर्जी द्वारा दायर इस मामले में ममता बनर्जी खुद अधिवक्ता के रूप में जिरह करने सुबह करीब 11 बजे हाई कोर्ट पहुंची थीं। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद बंगाल में भाजपा पहली बार सत्ता में आई है। चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई जिलों में हिंसा, आगजनी और राजनीतिक हमलों के आरोप लगे थे, जिनको लेकर विभिन्न याचिकाएं अदालत में दायर की गईं। तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह बंगाल के लोगों को कठिन समय में कभी अकेला नहीं छोड़तीं। पार्टी ने कहा कि सत्य, न्याय और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई में वह लगातार अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती हैं। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने साल 1982 में जोगेश चंद्र ला कालेज से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। उनके पास कला में स्नातक, बीएड तथा स्नातकोत्तर की डिग्रियां भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदालत में ममता बनर्जी की यह सक्रिय मौजूदगी केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम संदेश देने वाली है। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे *राजनीतिक नाटक* करार देते हुए चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग दोहराई है।

तालिबान ने दिया भारत ...

अफगानिस्तान पर भारी दबाव है। लेकिन ऐसे नाजुक मोड़ पर भारत खामोश नहीं बैठा। भारत ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि विकास और विश्वास से दिया है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। भारतीय कंपनी टीसीआरसी ने अफगान नेशनल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एएनएसए के साथ एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की है। अगले 5 सालों तक भारत अफगानिस्तान के काबुल समेत नौ सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर पॉइंट्स पर हाईटेक अत्याधुनिक लेबोरेटरी ? यानी लैब्स का जाल बिछा देगा। अब तक अफगानिस्तान में जो भी सामान आता था या वहां से बाहर जाता था उसकी क्वालिटी जांचने का कोई पुख्ता सिस्टम था ही नहीं। अब भारत की तकनीक, भारत की टेक्नोलॉजी से वहां भोजन, दवाएं, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, टेक्सटाइल और बिजली के सामानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होगी। भारतीय कंपनी सिर्फ मशीनें नहीं लगाएंगी बल्कि पूरे सिस्टम को जो बॉर्डर एरिया के हैं उनको अपग्रेड करेंगी। अफगान स्टाफ को ट्रेनिंग भी देंगी और उन्हें आईसीओ सर्टिफिकेशन तक लेकर जाएंगी। मतलब अब दुनिया का कोई भी देश अफगान माल को लो क्वालिटी कहकर रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। भारत ने अफगानिस्तान के हाथों में वो ताकत की चाबी दे दी है जिससे वो दुनिया के बाजारों में अपनी शर्तों पर अब व्यापार करने उतर चुका है। वो खुद को मुस्लिम उमा का रहनुमा बताता है। सच्चाई यह है कि आज अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ा कांटा वही बना हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान हमेशा उस पर निर्भर रहे, डिपेंडेंट रहे। लेकिन भारत ने चाबहार और अब इन लैब्स के जरिए पाकिस्तान के उस ट्रांजिट फ्रूट के घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। एएनएसए के प्रमुख फैजुल्लाह तमीम साहब ने कैमरे पर आकर भारत का शुक्रिया अदा किया।

पश्चिम बंगाल : सरकारी...

रथेंद्र बोस के नामांकन के बारे में भी बात की और परंपरा के अनुसार सर्वसम्मति बनाए रखने का आग्रह किया। बोस की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे इस भूमिका में प्रशासनिक समझ और संगठनात्मक अनुभव दोनों लेकर आएंगे। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कभी विधायक, मंत्री या अध्यक्ष जैसे किसी पद के लिए आवेदन नहीं किया। पार्टी ने उनकी निष्ठा को पहचाना है। वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए उनमें आवश्यक क्षमता है। हम उनके नेतृत्व के लिए सभी पक्षों से सहयोग चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष से संसदीय परंपरा का पालन करते हुए निर्विरोध स्पीकर चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्पीकर का चुनाव पारंपरिक रूप से सर्वसम्मति से होता आया है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष इस परंपरा को जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि स्पीकर का चुनाव शुक्रवार को सुबह 11 बजे होगा। पार्टी सूत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि रथेंद्र बोस ने हाल ही में हुए चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंद्वी को 23,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। 2026 के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने भाजपा को निर्णायक जनादेश दिया है, जिसने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज की है। यह उस राज्य में एक बड़ा बदलाव है जहां पिछले चुनाव में भाजपा को केवल 77 सीटें मिली थीं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), जिसने पिछले विधानसभा चुनावों में 212 सीटें जीती थीं, 80 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।

दिल्ली के सरकारी ...

दायित्व है कि वह संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए हैं। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सप्ताह में दो दिन *वर्क फ्रॉम होम* व्यवस्था लागू की जाएगी। निजी कंपनियों और संस्थानों को भी अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी जा रही है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो हेल्प डेस्क व कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही सरकार बड़ी कंपनियों और संस्थानों से व्यक्तिगत स्तर पर संवाद कर सहयोग सुनिश्चित करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उन आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जो सीधे जन-सुविधाओं और सार्वजनिक कार्यों से जुड़ी हैं। इनमें पब्लिक डीलिंग से संबंधित विभाग, फायर सर्विस, अस्पताल, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, बिजली एवं जल आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों के उपयोग को न्यूनतम किया जाएगा। नए निर्णय के अनुसार अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। जिन वाहनों की पहले 200 लीटर पेट्रोल की सीमा थी, उसे घटाकर 160 लीटर तथा 250 लीटर की सीमा को घटाकर 200 लीटर किया गया है। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को *मेट्रो मंडे* के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जहां तक संभव होगा, मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि दिल्ली नगर निगम कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9 से शाम 5:30 बजे है।

जल्द ही फिर से शुरू...

साझा सीमा पर शेष मतभेदों को सुलझाने के लिए जारी प्रयासों के बीच उन्होंने गए टिप्पणी की है। सांग्मा ने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए संवाद ही सर्वोत्तम मार्ग है, और दोनों सरकारों की रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

कानूनी बाधाएं दूर ...

रुपए की मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी मंदिर पुनर्विकास पहलों में से एक है और इसका उद्देश्य देश के सबसे पूजनीय शक्ति पीठों में से एक, ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर के आसपास के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर में भीड़भाड़ कम करना और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाना है, विशेष रूप से वार्षिक अंबुबाची मेले जैसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों के दौरान, जब लाखों तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने आते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुनर्विकास योजना में तीन स्तरीय गलियारे का निर्माण और मौजूदा पहुंच मार्गों की वर्तमान चौड़ाई लगभग 8-10 फीट से बढ़ाकर लगभग 27-30 फीट करना शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर के आसपास के खुले स्थान को लगभग 3,000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 1 लाख वर्ग फुट से अधिक करना भी है। यह कॉरिडोर परियोजना पीएम-डेवीआईएनई योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है। नीलाचल पहाड़ी पर स्थित मंदिर की विरासत संरचनाओं और भूमिगत जल स्रोतों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताते हुए याचिकाएं दायर किए जाने के बाद, पुनर्विकास पहल को पहले कानूनी और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, इस साल फरवरी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और भारतीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय और संरचनात्मक चिंताओं का समाधान किया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि संशोधित परियोजना योजना मंदिर की विरासत को संरक्षित करते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगी।

यूसीसी का विरोध कर कांग्रेस समेत विपक्ष भविष्य में मियां वोट भी खो देगा : दिलीप सैकिया

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। दिलीप सैकिया ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यूसीसी का विरोध करके कांग्रेस समेत विपक्षी दल भविष्य में उन मियां वोटों को भी खो देंगे, जो उन्हें अब तक मिलते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार राजनीतिक झटके मिलने के बावजूद विपक्ष जनता की भावना को समझने में विफल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नाव डूब जाने के बाद भी वे छप्पर से नीचे नहीं उतरते। सैकिया ने कहा कि राजनीतिक अवसान के बाद भी विपक्ष जनता के मन की बात नहीं समझ पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और रायजर दल के प्रमुख अखिल गोगोई यूसीसी का विरोध कर केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।

मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने कहा
नागा और कुकी समुदायों के 38 से अधिक लोगों को विभिन्न समूहों ने बंधक बना रखा

इंफाल। मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने गुरुवार को कहा कि नागा और कुकी समुदायों से संबंधित 38 से अधिक लोगों को राज्य भर में विभिन्न समूहों द्वारा बंधक बना लिया गया है। यह घटना मणिपुर में बुधवार को ताजा हिंसा भड़कने के बाद घटी है, जब कांगपोकपी जिले में सशस्त्र उग्रवादियों द्वारा कुकी समुदाय के तीन चर्च नेताओं और एक नागरिक सहित चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना इम्फाल-तामेंगलोंग राजमार्ग पर कोटलेन और कोटजिम गांवों के बीच सुबह लगभग 10 बजे घटी। पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कथित तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक नेताओं के साथ समन्वय कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के कुल 38 से अधिक लोगों को विभिन्न समूहों द्वारा हिरासत में लिया गया है।

हम उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज समूहों और राजनीतिक नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। कोंथौजम ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्थिति की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया है और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। हमें संदेह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने देना चाहते। केंद्रीय मंत्री ने नोनी में मृतक नागरिक के परिवार से मुलाकात के दौरान ये टिप्पणियां कीं। उनके साथ तीन नागा विधायक भी थे। वे इम्फाल पूर्वी जिले के जेएनआईएमएस अस्पताल गए, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को कांगपोकपी जिले के कोटलेन और कोटजिम क्षेत्रों के बीच नागरिकों के एक समूह पर सशस्त्र बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी की कड़ी निंदा की, जिसमें तीन लोग मारे गए और चार अन्य घायल हो गए। बुधवार को पूर्वोत्तर के तीन बैपटिस्ट चर्च नेताओं की हत्या के बाद पूरे राज्य से निंदा व्यक्त की गई, जिसमें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) और नागा विधानमंडल फोरम (एनएलएफ) ने हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय की मांग की।

लंका में 31 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

होजाई (हिंस)। असम के होजाई जिले के लंका इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए एक अभियान के दौरान 31 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान एक बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने आज बताया कि गिरफ्तार तस्कर की पहचान अभिराम कर्मकार के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित को लंका गोरू बाजार इलाके से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने गांजे के पैकेट राजीव नामक एक व्यक्ति से लिए थे। यह अभियान समजिला पुलिस अधीक्षक प्लावन नाथ के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने एएस-31ए-0321 नंबर की एक बाइक भी जब्त की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

पवन खेड़ा कांग्रेस के लिए आत्मघाती बम अब बम का चल रहा परीक्षण : भूपेन बोरा

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित भाजपा विधायक भूपेन बोरा ने गुरुवार को कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पवन खेड़ा कांग्रेस के लिए एक *आत्मघाती बम* हैं और अब उस *बम* का परीक्षण चल रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेन बोरा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नगांव लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा देने का प्रयास कर रही है। भाजपा विधायक ने कहा कि राज्य सरकार 26 मई को विधानसभा में यूसीसी पेश करेगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह और बेटियों को संपत्ति अधिकार समेत कई

महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जाएंगे। भूपेन बोरा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और राइजर दल के प्रमुख अखिल गोगोई की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता सरकार द्वारा बहुविवाह के खिलाफ उठाए गए कदमों का विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे पर उनकी भूमिका खिलंजिया (लोकल) विरोधी है।

तेल टैंकर से 28 मवेशी जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

मोरीगांव (हिंस)। मोरीगांव जिला के जागीरोड पुलिस थाना क्षेत्र इलाके में पुलिस द्वारा चलाए गये अभियान के दौरान एक तेल टैंकर से 24 मवेशियों को बरामद किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर चलाए गए अभियान के दौरान तेल टैंकर (एएस-05सी-1034) से 24 मवेशियों को बरामद किया गया। मवेशियों को बड़े ही शातिर तरीके से तेल टैंकर के भीतर छुपा कर मेघालय भेजा जा रहा था। इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान लखीमपुर जिले के मोहम्मद शरीफूल अली, मोहम्मद अलाउद्दीन और नगांव के मोहम्मद मुजम्मिल हक के रूप में की गई है। पुलिस इस संबंध में पशु अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर तीनों पशु तस्करों से सघन पूछताछ कर रही है। ज्ञात हो की राज्य में सख्त पशु अधिनियम लागू है, इसके बावजूद पशुओं की तस्करी जारी है।

21 करोड़ की हेरोइन व अफीम के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। असम में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कामरूप पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अमीनगांव में एक बस से करीब 21 करोड़ 36 लाख मूल्य की हेरोइन और अफीम बरामद की है। इस मामले में पांच कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस के सीपीआरओ ने गुरवार को बताया कि, गुप्त सूचना मिली थी कि मणिपुर के क्वाक्टा से पड़ोसी राज्य की ओर जा रही बस संख्या एएस 06 एसी 7555 के जरिए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना में यह भी बताया गया था कि बस में कोई सामान्य यात्री नहीं है और उसमें केवल तस्कर सवार हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अमीनगांव में बस को रोककर तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान बस में बने गुप्त खाने से 197 साबुन के डिब्बों में छिपाकर रखी गई 2.561 किलो हेरोइन और 8 किलो अफीम बरामद की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में अब्दुल लतीफ (33), मोहम्मद ताहेर अली (38), मोहम्मद इस्लामुद्दीन (38), मोहम्मद लतीप (30) और मोहम्मद अजमेर (37) को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और नेटवर्क के विस्तार का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

ईंधन बचत के लिए त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, आधे कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

अगरतला (हिंस)। त्रिपुरा में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और लोगों को किसी प्रकार की घबराहट या अनावश्यक खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। यह बातें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने गुरुवार को कही। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अनावश्यक रूप से सोना और ईंधन नहीं खरीदने तथा ईंधन का सीमित उपयोग करने की अपील की है। इसी दिशा में त्रिपुरा सरकार ने भी कदम उठाते हुए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है, ताकि ईंधन की बचत की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश हमेशा सोच-समझकर लिए जाते हैं। उन्होंने कोविड-19 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह की कई सावधानियां अपनाने की अपील की थी, जिसका लोगों ने पालन किया था। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है, जिससे साफ है कि आम लोग भी ईंधन बचाने को लेकर जागरूक हो रहे हैं। गुवाहाटी से लौटने के बाद

मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और इसके बाद प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुए बिना ईंधन बचत के उपाय लागू किए गए। माणिक साहा ने कहा कि देश को ईंधन आयात को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार और आम जनता दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि देश जल्द ही वर्तमान परिस्थितियों से बाहर निकल आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और फिलहाल राशनिंग को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कामाख्या मंदिर में किए दर्शन

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज कामाख्या धाम पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर स्थित मंदिर में मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख-समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं एवं मंदिर प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि कामाख्या मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शर्मा मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद आज पहली बार कामाख्या धाम में पहुंचे। वहीं कामाख्या धाम प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया।

अरुणाचल प्रदेश : वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार कस्तूरी मृग कैमरे में हुआ कैद

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में स्थित योर्डी राबे सुप्से वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर कस्तूरी मृग की पहली बार कैमरे में कैद की गई तस्वीर शोधकर्ताओं ने रिकॉर्ड की है, जिसे पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में वन्यजीव प्रलेखन के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम सियांग के वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभयारण्य के अंदर गहराई में लगाए गए कैमरा ट्रैप के माध्यम से हाल ही में इस दुर्लभ जानवर की तस्वीर ली गई थी, जो अपने घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाले इलाकों के लिए जाना जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने इस घटना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि कस्तूरी मृग मायावी, निशाचर जानवर होते हैं जो जंगल में शायद ही कभी देखे जाते हैं। उनकी उपस्थिति को अक्सर एक स्वस्थ और अपेक्षाकृत अबाधित उच्च-ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक माना जाता है। इस बीच, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मीन ने इस खोज को राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि योर्डी राबे सुप्से (वाईआरएस) वन्यजीव अभ्यारण्य से कस्तूरी मृग की पहली कैमरा-ट्रैप छवि अरुणाचल प्रदेश के लिए सवन्यजीवसंरक्षण में एक महत्वपूर्ण सफलता है। उन्होंने आगे कहा कि यह खोज हमारे उच्च ऊंचाई वाले जंगलों की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है और पूर्वी हिमालय में निरंतर संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को उजागर करती है। उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र की वन्यजीव विरासत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में शामिल शोधकर्ताओं, वन अधिकारियों और अन्य हितधारकों के प्रयासों की भी सराहना की।

नगांव में टाटा आईपीएल फैन पार्क का दो दिवसीय आयोजन 16 से

नगांव (निसं)। आगामी 16 और 17 मई को नगांव के नुरुल अमीन स्टेडियम में आयोजित होने वाले टाटा आईपीएल फैन पार्क में आईपीएल मैचों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसे लेकर आज नगांव क्रीड़ा संस्था के स्पोर्ट्स क्लब पवेलियन के सभाकक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बीसीसीआई के आईपीएल फ्रेंचाइजी के सीनियर ऑपरेटर अमित सिद्धेश्वर ने बताया कि देश के जिन क्षेत्रों में आईपीएल के लिए पर्याप्त स्टेडियम सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां खेल के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 16 मई को शाम 6-30 बजे से तथा 17 मई को दोपहर 2-30 बजे और शाम 6-30 बजे आईपीएल मैचों का सीधा प्रसारण बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। फैन पार्क में दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों के मनोरंजन के लिए व्हिसलिंग, चीयरिंग, फेस पेंटिंग, शाउट आउट और क्रेजी स्टंट जैसी कई आकर्षक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे प्रशंसक उत्साहपूर्ण माहौल में आईपीएल का आनंद ले सकेंगे।

असम में घुसपैठ कर रहे 12 बांग्लादेशियों को रोका गया : मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और असम पुलिस ने 12 कथित घुसपैठियों को असम में घुसपैठ करने से रोक दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह अभियान बीती मध्य रात्रि के ठीक बाद चलाया गया था, जो राज्य में अवैध घुसपैठ पर चल रही कड़ी कार्रवाई का ही एक हिस्सा है। डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 12-20 बजे, असम पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर घुसपैठियों की हलचल को रोका और 12 अवैध लोगों को असम में घुसने से रोक दिया। हालांकि, राज्य के किस हिस्से से घुसपैठ हो रही थी, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि असम सरकार अवैध प्रवासन और घुसपैठ के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव के खिलाफ अपनी सख्त *जीरो टॉलरेंस* की नीति को जारी रखेगी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब असम सरकार सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय चिंताओं पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है, खासकर बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में।

एचपीवी वैक्सीन को लेकर नगांव जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक
14-15 वर्ष की सभी किशोरियों से निःसंकोच टीका लेने की जिला आयुक्त की अपील

नगांव (निसं)। महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए दिए जा रहे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान की समीक्षा के उद्देश्य से आज नगांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक खंड की कार्य दक्षता पर चर्चा की गई। जिन ब्लॉकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनकी सफलता के साथ-साथ कमजोर प्रदर्शन वाले ब्लॉकों की समस्याओं की भी समीक्षा की गई। जिला आयुक्त ने छात्राओं, विद्यालयों के शिक्षकों तथा अभिभावकों के बीच इस टीकाकरण के सकारात्मक प्रभाव को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अभियान के शेष दिनों के लिए ब्लॉकवार दैनिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण

विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा कार्यक्रमों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया गया। जिला आयुक्त ने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और कैंसर प्रभावित राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कुछ भ्रामक प्रचार के कारण किशोरियां इस महत्वपूर्ण टीके से वंचित न रहें, इसके लिए व्यापक और सही जनजागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। जिला आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त (स्वास्थ्य) कमलजीत शर्मा, संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जिला टीकाकरण अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नगांव मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सभी उपखंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक टीमों के सदस्य, डीसीएम, यूएनडीपी के समन्वयक तथा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की संभावना को रोकने में सहायक यह टीकाकरण कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी में असम में आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विकास शर्मा ने जानकारी दी कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को यह टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। छात्राओं और अभिभावकों से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने का आग्रह किया गया है।

অসম লোকসেৱা আয়োগ
ASSAM PUBLIC SERVICE COMMISSION
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-781022.
No.304PSC/DR-57/1/2023-24

NOTIFICATION

It is for information to all concerned that the Assam Public Service Commission will hold the Interview/Viva-Voce for the following post published vide **Advt. No.11/2024, dated: 01-06-2024** as per programme given below at its office at Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-22.

Sl. No.	Name of the Post & Department	Date of Interview / Viva-Voce	Reporting Time
1	**Under Secretary to the Govt. of Assam, Judicial Deptt.**	**25-05-2026**	**9.30 AM**
2	**Junior Legislative Counsel and Under Secretary to the Govt. of Assam, Legislative Deptt.**	**30-05-2026**	**9.30 AM**
3	**Legal Assistant to Legal Remembrancer and Under Secretary to the Govt. of Assam, Judicial Deptt.**	**05-06-2026**	**9.30 AM**

Kindly note that the candidates appearing the interview/viva-voce **must bring the following original testimonials in chronological order on the day of the interview :**

i. H.S.L.C/H.S Admit/Pass Certificate reflecting date of birth.
ii. H.S.L.C Marksheet and Pass Certificate.
iii. H.S.S.L.C Marksheet and Pass Certificate.
iv. Bachelor of Law Degree (all semesters) Marksheets and Pass certificate
v. Certificate of Enrolment by Bar Council.
vi. Certificate of Practice by Bar Council
vii. Experience Certificate (Minimum 3 years)
viii. CGPA Conversion Formula of the respective universities
ix. Permanent Residential Certificate/Employment Exchange Registration.
x. State Government Employees of Assam must submit No Objection Certificate from their respective employer or Permanent Residential Certificate/ Employment Exchange Registration
xi. Caste/PwBD certificate/BPL Card (if applicable).
xii. Declaration Form A *("May be downloaded from APSC's website")*
xiii. **Candidates with documents having inconsistencies in name, father's name etc., must be supported by an affidavit addressing and affirming the correct details.** *(if applicable)*
xiv. Any other documents that may be relevant for their candidature.

This is to be noted that relevant documents obtained by the candidates till the last date of submission of online application i.e. 05-07-2024 will be accepted for further consideration.

The intimation letters shall be uploaded on 20-05-2026 in the APSC's website (www.apsc.nic.in). No intimation letter to the eligible candidates shall be sent separately by post. The candidates shall have to download their own intimation letter from the aforesaid website.

Sd/-
Secretary,
Assam Public Service Commission
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-22

-- DIPR /D/VBS-14/15-May-26

संपादकीय

'पेपर लीक' का माफिया कौन?

एक बार फिर 'पेपरलीक' और करीब 23 लाख युवा बच्चों का भविष्य अधर में, अंधकारपूर्ण और अनिश्चित... ! 'नीट' का पेपर लीक हुआ है। अभ्यर्थी युवाओं में कई होनहार, विशेषज्ञ डॉक्टर बन सकते थे! जिंदगियां बचा सकते थे! घर-परिवार की आर्थिक स्थितियां बेहतर कर सकते थे! मां-बाप के कर्ज चुकता कर सकते थे! लेकिन एक माफिया, संगठित गिरोह, पैसे के हवसी, संवेदनहीन साजिशकार इस देश में सक्रिय हैं, जो युवा पीढ़ी को बार-बार निराश, हताश कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें छीन रहे हैं। विडंबना यह है कि बीते सालों में 70 बार या अधिक पेपरलीक कराए गए हैं, कुछ 'काली भेड़ें' जेल में हो सकती हैं, लेकिन सरगना बेखौफ, बेलगाम षड्यंत्र रच रहे हैं। आज तक न तो सीबीआई और न ही सरकारी की अन्य एजेंसियां इस नापाक नेटवर्क के 'माफिया' को तय नहीं कर पाई हैं। बेशक सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। कानून में सजा कितनी है-3, 4, 5 अथवा 10 साल तक। किसको सजा दी गई? किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंका गया? किस पर स्थायी पाबंदी लगाई गई? इन सवालों के जवाब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देने चाहिए। हकीकत यह है कि यह शर्मनाक, देशद्रोही धंधा आज हजारों करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। क्या इन साजिशकारों के घरों में युवा बच्चे नहीं हैं? वे भी डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते होंगे! शायद उनके साथ ऐसे हादसे नहीं हुए या उनके बच्चे भी पेपरलीक के जरिए पास हो गए होंगे! पेपरलीक का धंधा तो शाश्वत लगता है हमें! भारत जैसे विराट, सम्मानित और विश्व-गुरु की खुशफहमी पाले देश के लिए ये करतूतें, हरकतें, युवा पीढ़ी के सपनों को चकनाचूर करने वाली 'माफियागीरी' शर्मनाक ही नहीं, बल्कि इसका दमन भी आतंकवाद, नक्सलवाद की तरह किया जाना चाहिए। दरअसल मौजूदा शिक्षा मंत्री नालायक हैं, शिक्षा मंत्रालय नकारा, भ्रष्ट है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) बार-बार साबित हो रही है कि वह पारदर्शी, ईमानदार, लीक-मुक्त परीक्षाएं कराने के लायक ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बेहद जागरूक और पारदर्शी नेता हैं, ऐसे निकम्मेपन के खिलाफ माने जाते रहे हैं, लिहाजा मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलें। अंततः युवा पीढ़ी और जनता को सड़कों पर बिछ कर जन-आंदोलन छेड़ना करना पड़ेगा। यह सिर्फ 23 लाख बच्चों के भविष्य का ही नहीं, बल्कि 23 लाख परिवारों के भविष्य पर आघात किया गया है। अधिकांश बच्चे गरीब या निम्न मध्यवर्गीय होते हैं। जिन बच्चों ने 10-28 लाख रुपए में लीक वाले प्रश्नपत्र खरीदे जाते हैं, उस जमात को छोड़ दीजिए। दरअसल वे ही पेपरलीक के धंधे के थोक-ग्राहक हैं, लिहाजा इस शर्मनाक धंधे के सह-भागीदार हैं। हमने चार दशक से अधिक की पत्रकारिता के दौरान पेपर और भ्रष्टाचार के मामले देखे हैं, कवर किए हैं। नकदी के बंडलों के लेन-देन देखे हैं। उनमें कुलपति, रजिस्ट्रार से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक की 'मिलीभगत' भी देखी है, लिहाजा पेपरलीक के बीच में प्रिंटिंग प्रेस और उसके दल्लों की धंधेबाजी और नतीजतन पेपरलीक कमोबेश हमें नहीं चौंकाता। अब इस नेटवर्क को तोड़ने और मसलने का वक्त आ गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट के खास, समझदार मंत्रियों को विमर्श कर यह तय करना पड़ेगा कि परीक्षा का तरीका क्या होना चाहिए? ऑफलाइन परीक्षा क्यों जरूरी है? डिजिटल के दौर में कई परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। अब 'नीट' का पेपरलीक हुआ है, तो 400-500 करोड़ रुपए पर पानी फिर गया। यह करदाता का पैसा था। बताया जा रहा है कि एक गैस पेपर बीते 15-30 दिनों से घूम रहा था। वह 150 पन्नों का था, जिसमें 410 प्रश्न संकलित किए गए थे। उनमें 120-140 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए। बॉयलॉजी के तो 90 प्रश्न और रसायन विज्ञान के 45 प्रश्न परीक्षा में आ गए, मानो गैस पेपर की 'फोटोप्रति' की गई हो! सीबीआई जांच करेगी कि यह कैसे और क्यों हो सकता है? अनुमानित पेपर के नाम पर पुस्तिकाएं बाजार में बिकती रही हैं, लेकिन इतना मिलान, हूबहू होना सवालिया और संदेहजनक है। परीक्षा रद्द करना कोई समाधान नहीं है।

> अभ्यर्थी युवाओं में कई होनहार, विशेषज्ञ डॉक्टर बन सकते थे! जिंदगियां बचा सकते थे! घर-परिवार की आर्थिक स्थितियां बेहतर कर सकते थे! मां-बाप के कर्ज चुकता कर सकते थे! लेकिन एक माफिया, संगठित गिरोह, पैसे के हवसी, संवेदनहीन साजिशकार इस देश में सक्रिय हैं, जो युवा पीढ़ी को बार-बार निराश, हताश कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें छीन रहे हैं। विडंबना यह है कि बीते सालों में 70 बार या अधिक पेपरलीक कराए गए हैं, कुछ 'काली भेड़ें' जेल में हो सकती हैं, लेकिन सरगना बेखौफ, बेलगाम षड्यंत्र रच रहे हैं। आज तक न तो सीबीआई और न ही सरकारी की अन्य एजेंसियां इस नापाक नेटवर्क के 'माफिया' को तय नहीं कर पाई हैं। बेशक सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। कानून में सजा कितनी है-3, 4, 5 अथवा 10 साल तक। किसको सजा दी गई? किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंका गया? किस पर स्थायी पाबंदी लगाई गई? इन सवालों के जवाब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देने चाहिए। हकीकत यह है कि यह शर्मनाक, देशद्रोही धंधा आज हजारों करोड़ रुपए का बताया जा रहा है।

कुछ अलग

धरना-प्रदर्शन का ककहरा

आपको कितने दिन हो गए, सड़क पर धरना लगाए?' उन्होंने हमें पूछा था। अब ऐसी बातों का भी भला कोई जवाब हो सकता है। बहुत कोंचोगे तो यही जवाब देंगे कि 'साब सड़क पर तो हमारा हमेशा धरना रहा है, आप हमारे धरने के दिन न गिनिये। कोशिश कीजिए कि साम, दाम, दंड, भेद की कोई भी नीति अपनाकर यह धरना उठाना है।' हमारा यह धरना वैसे अभी नहीं, बहुत दिन से है। हमने तो शिक्षा-दीक्षा हासिल करने की बजाय धरने प्रदर्शन का ककहरा पढ़ा है। हमारी सुनवाई ही कहां होती है धरना, प्रदर्शन के बिना। जब होश संभाली तो पता चला कि यहां अक्ल की नहीं, सिफारिश और सिक्कों की चमक देखी जाती है। जब इसके धनुर्धारी इस सब सीटों को हथिया लेते हैं, तो हमारे लिए जो बचता है, वह है सड़कछाप पाठशाला और शैक्षिक संकट में घिरे हुए विश्वविद्यालय, जिसके उपकुलपति आर्थिक तंगी से परेशान होकर इस्तीफा भी दे जाएं तो किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। एक अनार है और सौ बीमार हैं। एक इस्तीफा देकर अनोखा कार्य करता है तो बाईस उसकी जगह लेने को तैयार बैठे हैं। लोग तो भई आजकल गद्दी छोड़ते कहां हैं? जाने की तैयारी कर भी लें तो अपना नाती-पोता वहां भिड़ा जाते हैं। ये साब बीते युग के आदर्शों का रोना रोते हुए इस्तीफा दे गए तो इनकी अक्ल का मातम ही मनाया जा सकता है। देखो न एक भी हाथ उनके समर्थन में नहीं उठा, किसी समूह ने उनके हक में धरना नहीं लगाया। वे लोग, जब से होश संभाली, अपने साथ होती ऊंच-नीच के विरोध में धरना लगाने की बस सोचते रहे हैं, लेकिन ऐसी बातों पर भी कोई धरना लगाता है कि आपको सही जगह पढने के लिए नहीं मिली।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस (15 मई) पर विशेष

असमानताओं के दौर में परिवार और संस्कारों की चुनौती

योगेश कुमार गोयल

> समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई (परिवार) के अस्तित्व, उसकी चुनौतियों और उसकी अपरिहार्यता पर आत्ममंथन करने का अवसर है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिन आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय 'परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण' रखा गया है। यह विषय सीधे तौर पर उन सामाजिक और आर्थिक विषमताओं पर प्रहार करता है, जो आज के वैश्विक परिदृश्य में परिवारों की संरचना और बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं।

प्रत्येक वर्ष 15 मई को विश्वभर में 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई (परिवार) के अस्तित्व, उसकी चुनौतियों और उसकी अपरिहार्यता पर आत्ममंथन करने का अवसर है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिन आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय 'परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण' रखा गया है। यह विषय सीधे तौर पर उन सामाजिक और आर्थिक विषमताओं पर प्रहार करता है, जो आज के वैश्विक परिदृश्य में परिवारों की संरचना और बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। भारतीय संदर्भ में, जहां परिवार को केवल एक संस्था नहीं बल्कि 'संस्कारों की पाठशाला' माना जाता है, वहां इस वर्ष की थीम एक गंभीर विमर्श की मांग करती है।

भारतीय सभ्यता में परिवार का आधार प्रेम, त्याग और सह-अस्तित्व रहा है। पश्चिमी देशों में जहां परिवार अक्सर एक संविदा की तरह देखा जाता है, वहीं भारत में यह एक आध्यात्मिक बंधन है। हमारे यहां 'मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः' के आदर्शों ने नई पीढ़ी को अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ होना सिखाया। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता 'संयुक्त परिवार' रही है। एक ही छत के नीचे तीन-चार पीढ़ियों का साथ रहना बच्चों के लिए सुरक्षा कवच और बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक आश्रय सुनिश्चित करता था। यहां 'मैं' की जगह 'हम' की प्रधानता थी। इस व्यवस्था में 'वसुधैव कुटुंबकम' (संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है) का भाव निहित था, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक कल्याण के बारे में सोचता था।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में 'परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण' का विषय अत्यंत सामयिक है। आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक और डिजिटल विभाजन ने परिवारों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। जब एक परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित होता है तो उसका सबसे पहला और सीधा प्रभाव बच्चों के पोषण और शिक्षा पर पड़ता है। आय की अस्थिरता परिवारों को तनाव में डालती है, जिससे

घर का वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है। 2026 का आयोजन इसी बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अपर्याप्त सहायता प्रणालियां गरीब परिवारों को वंचितता के चक्र में धकेल देती हैं। जहां तक बाल कल्याण और भविष्य की संभावनाओं की बात है तो बाल कल्याण केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है। इसमें बच्चे का मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास शामिल है। असमानताओं के कारण कुछ बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं जबकि एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता है। यह 'अवसरों की असमानता' आने वाली पीढ़ियों की उत्पादकता और सामाजिक गतिशीलता को अवरुद्ध कर देती है। आधुनिक युग में सूचना और तकनीक तक पहुंच भी एक बड़ी असमानता है। जिन परिवारों के पास डिजिटल संसाधन नहीं हैं, वहां के बच्चे वैश्विक दौड़ में पीछे छूट रहे हैं।

आज हम एक ऐसे संक्रमण काल में हैं, जहां तकनीक ने दूरियों को तो कम किया है लेकिन दिलों के बीच की दूरियां बढ़ा दी हैं। शहरीकरण और भौतिकवाद की अंधी दौड़ ने भारतीय परिवार की पारंपरिक संरचना को हिलाकर रख दिया है। पहले भोजन की मेज पर दिनभर की बातें साझा होती थी लेकिन आज वहां मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकती है। तकनीक ने सुविधा तो दी मगर संवेदनाएं छीन ली। लोग एक ही कमरे में रहकर भी अलग-अलग आभासी दुनिया में खोए रहते हैं। बुजुर्ग भी, जो कभी परिवार की धुरी होते थे, आज हाशिए पर हैं। आधुनिक पीढ़ी अपनी निजता और स्वतंत्रता के नाम पर बड़ों के अनुभव और मार्गदर्शन को बोझ समझने लगी है।

भारत में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या एक चिंताजनक सामाजिक संकेत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में वरिष्ठ नागरिक गृहों की मांग और संख्या दोनों बढ़ रही है। जिस संस्कृति में श्रवण कुमार जैसे उदाहरण दिए जाते थे, वहां आज बुजुर्ग अकेलेपन और भावनात्मक उपेक्षा का शिकार हैं। संतानों द्वारा आर्थिक मदद तो भेज दी जाती है लेकिन बुजुर्गों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है] 'समय और अपनापन', वह उन्हें नहीं मिल पाता। यह स्थिति न केवल बुजुर्गों के लिए मानसिक अवसाद पैदा करती है बल्कि नई पीढ़ी को भी उन संस्कारों से वंचित कर देती है, जो केवल बड़ों के सान्निध्य में सीखे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 इस बात पर जोर देता है कि सरकारों को परिवार-केंद्रित नीतियां बनानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत परिवारों को गरीबी से बचाने के लिए बाल और परिवार लाभ, किफायती शिशु देखभाल और माता-पिता के लिए वैतनिक अवकाश जैसी नीतियां अनिवार्य हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय सुरक्षा को मिलाकर एक ऐसा ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे असमानता के प्रभाव को कम किया जा सके। कॉरपोरेट जगत और सरकारों को ऐसी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, जहां कर्मचारी अपने परिवार को पर्याप्त समय दे सकें।

यदि हमें एक स्वस्थ और स्थिर समाज का निर्माण करना है तो हमें अपनी पारिवारिक जड़ों की ओर लौटना होगा। परिवार समाज की मूल इकाई है और यदि नींव कमजोर होगी तो राष्ट्र की इमारत सुरक्षित नहीं रह सकती। शिक्षा का उद्देश्य केवल आर्थिक सफलता नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का विकास भी होना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि सफलता का असली पैमाना रिश्तों की मजबूती है। परिवारों को 'डिजिटल डिटॉक्स' अपनाने की जरूरत है। दिन का कुछ समय केवल परिवार के सदस्यों के साथ बिना किसी उपकरण के बिताना चाहिए। परिवार के निर्णयों में बुजुर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके अनुभव हमारे जीवन के कठिन मोड़ों पर रोशनी दिखाने का काम करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें स्मरण कराता है कि भले ही दुनिया बदल रही हो, तकनीक उन्नत हो रही हो लेकिन एक मनुष्य के लिए परिवार की आत्मीयता का कोई विकल्प नहीं है। 'परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण' का संदेश तभी सफल होगा, जब हम समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को कम करने के साथ-साथ अपने भीतर के प्रेम और करुणा को भी जगाएंगे। भारतीय संस्कृति का 'हम' का भाव और वैश्विक समाज की न्यायसंगत नीतियां मिलकर ही एक ऐसी दुनिया बना सकती हैं, जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, हर बुजुर्ग सम्मानित हो और हर परिवार समृद्ध हो। इस दिवस पर यह संकल्प लेना आवश्यक है कि हम अपने परिवार की गरिमा को बनाए रखेंगे और रिश्तों की इस अनमोल धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए सहेजकर रखेंगे। भारतीय संस्कृति में परिवार केवल एक साथ रहने का नाम नहीं है बल्कि एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का नाम है।

देश दुनीया से

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनफिंग की मुलाकात के कूटनीतिक मायने शेष दुनिया के लिए अहम

सफल कारोबारी से राजनेता बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हर रिश्ते को फायदे और नुकसान के नजरिये से देखते है, लेकिन कूटनीतिक इंजीनियर समझे जाने वाले चीन के अपने दौरे को लेकर उन्होंने केवल इतना भर कहा कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, वैश्विक रणनीतिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। चूंकि अमेरिका और चीन एक दूसरे के सहयोगी और प्रतिस्पर्धी दोनों समझे जाते हैं, इसलिए लगभग एक दशक के अन्तराल पर हुई उनकी यह यात्रा के कूटनीतिक मायने अहम समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी इस मुलाकात की सफलता और विफलता का असर पूरी दुनिया पर निःसंदेह पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले साल यानी अक्टूबर 2025 में जब आखिरी बार ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात हुई थी, तब उनके बीच मुख्य मुद्दा टैरिफ था, लेकिन अब बदलते वैश्विक हालात में जाहिर तौर पर ईरान भी होगा। क्योंकि पश्चिम एशिया संकट ने दोनों देशों के लिए मुश्किलें बढ़ाई है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि आपसी तनाव के बावजूद वे सहयोग का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। चूंकि लगभग एक दशक बाद यानी 2017 के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 2026 में चीन पहुंचा है। हालांकि, टैरिफ वॉर की वजह से माना जाता है कि ट्रंप का रुख पेइचिंग को लेकर कठोर है। समझा जाता है कि अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने यानी ट्रंफ ने चीन से होने वाले आयात पर टैरिफ की घोषणा की थी। जबकि दूसरे टर्म में वह इस लड़ाई को और आगे ले गए और 125% तक भारी भरकम टैरिफ तक जड़ दिया। हालांकि दुनियावी रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीनी नियंत्रण की वजह से आखिरकार ट्रंप को झुककर समझौता करना पड़ा था, अन्यथा उनका कारोबारी हित प्रभावित होता। ऐसे में टैरिफ वॉर भले थम गई हो, पर अमेरिका और चीन के बीच की पारस्परिक होड़ कायम है और वह नित्य नए स्वरूप में उभरकर सामने आ ही जाती है। चूंकि दोनों देश एक-दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं, पर इतना नहीं जिससे बात ज्यादा बिगड़े। हाल के अमेरिका/इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान भी कुछ यही देखने को मिला है। भले ही ईरान की आर्थिक व

सामरिक मदद के आरोप में अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की, और चीन ने भी पलटवार करते हुए वॉशिंगटन की नीतियों का विरोध किया, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में रहकर हुआ। इसकी ठोस वजह उनकी आपसी निर्भरता और पारस्परिक जरूरत भी है, जिसे समझने की जरूरत है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि चीन के लिए अमेरिका आज भी सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि इस साल चीनी निर्यात में करीब 10% की कमी आई है। चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह झटका है। दिलचस्प बात तो यह है कि खाड़ी देशों में भी चीन का निर्यात घटा है। मसलन, तेहरान (ईरान) का सबसे बड़ा तेल खरीदार होने के नाते भी उसकी परेशानी बढ़ रही है। लिहाजा चीन चाहता है कि युद्ध जल्दी थमे। भारत की भी यही सोच है। वहीं दूसरी ओर, ट्रंप को ईरान पर समर्थन और निवेश के लिए चीन चाहिए। इसीलिए वह अपने साथ कई बड़े उद्यमियों को लेकर बीजिंग पहुंचे हैं। चूंकि अमेरिका इस दौरे से बड़ी डील की उम्मीद कर रहा है, खासकर बोइंग विमानों की। इसलिए आलोचकों को डर है कि कहीं ताइवान पर ट्रंप नरम न पड़ जाएं। अमेरिकी हित में वह ऐसा कर सकते है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि इस समय दोनों रसूखदार नेता घरेलू मोर्चे पर विविध असहज स्थितियों में फंसे हुए हैं। लिहाजा उनकी कोशिश यही होगी कि इस मुलाकात से कुछ बड़ा हासिल किया जाए। यदि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पारस्परिक सहयोग के रास्ते पर बढ़ती है और ईरान में शांति कायम होती है, तो यूक्रेन सहित सभी का फायदा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे पर दुनियाभर की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में स्वाभाविक बात है कि भारत भी अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखेगा। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इससे जुड़े एक सवाल पर कहा भी है कि भारत के कई देशों के साथ रिश्ते है। कई देशों के साथ साझेदारी आगे बढ़ रही है। चूंकि विभिन्न देशों के बीच इस तरह का दौरा होता रहता है और जब भी इस तरह के दौरे होते हैं तो भारत देखता है कि उसमें क्या बदलाव आया है- या फिर क्या गतिविधियां हुई। ऐसा इसलिए किया जाता है कि राष्ट्रहित के अनुरूप नीतियां संशोधित होती रहें। चूंकि भारत हाल के वर्षों मे अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। दूसरी ओर चीन भी भारत का अहम पड़ोसी देश है, जिसके साथ सीमा विवाद के बाद भी रिश्ते व्यवहारिक समझ पर वापस लौट रहे है। ऐसे में दोनों देशों के आपसी संबंध और इस दौरे के निष्कर्ष भी भारत पर असर डालेगा। अमेरिका और चीन के रिश्ते एक लंबे वक्त तक असहजता के दायरे में रहे, जिसके जियोपॉलिटिकल प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा है। ट्रंप का यह दौरा 2017 के बाद हो रहा है। चीन पहुंचने पर बुधवार को ट्रंप का स्वागत उपराष्ट्रपति ने किया, जो 2017 से अच्छा स्वागत होने को दर्शाता है। चीन मामलो के जानकार बताते हैं कि भारत जानना चाहेगा कि ट्रंप और चिनफिंग के बीच बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला। हाल के वर्षों मे प्रशांत महासागर में जिस तरह चीन का प्रभाव बढ़ा है, इसी बैलेंस ऑफ पावर के मद्देनजर अमेरिका और भारत रणनीतिक और सामरिक मुद्दों पर लगातार नजदीकी स्तर पर काम करते रहे। ऐसे में अमेरिका और चीन अपने सबंधों को अगर फिर से नया आयाम देने का फैसला करते है तो अमेरिका व चीन दोनों के रिश्तों के मुताबिक भारत को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करना होगा।

आप का नजरीया

संकल्प के नक्शे पर

भाजपा ने एक साथ चार शहरों के नक्शे खींच दिए, तो जमाने को देखना होगा कि शहरीकरण के बाजार में कितनी हवा बाकी है। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन तक संकल्पों के घोड़े दौड़े हैं, तो समझना यह होगा कि आधुनिक हिमाचल की शिरकत क्या है। मंडी के भीतर और मंडी के बाहर दो तरह की सत्ताएं रही हैं। एक ने पिछले चुनाव के धरातल पर जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया, तो शहर के भीतर तक नगर निगम आया और दूसरे ने सांस्कृतिक विरासत ढूंढी, तो शिवधाम का मंजर नजर आया। इक्यासी मंदिरों की प्रदक्षिणा में सारे मंडी का जज्बा है, तो भाजपा ने पहली बार कसम खाई कि कुछ करके दिखाएगी। मंडी के अगल-बगल से लांघते पर्यटक को रोकना है, तो कसौटियों की बुनियाद पर मंडी को नगर निगम की सक्रियता चाहिए। अधोसंरचना निर्माण के वादे सामने आए हैं, तो याद रखना होगा कि शहर के सपनों को जिंदा रखना होता है। वर्षों पहले पंडित सुखराम ने इंदिरा मार्किट की परिकल्पना में जो एहसास शहर को दिया, क्या इस संकल्प के बाजुओं पर वैसा कोई अवतार है। बेशक कांग्रेस ने हमीरपुर और शिमला में दो बड़े व्यापारिक परिसर बनाने का संकल्प उतारा है, लेकिन देखना यह होगा कि इस स्तर की परियोजनाएं क्या सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला को मिलती हैं। सोलन में नगर निगम क्षेत्र को जो विजन भाजपा दे रही है, उसके अनुसार शहर की जलापूर्ति अब सही ढर्रे पर आएगी। सोलन के इर्द-गिर्द अब पहाडियां कम अपार्टमेंट अधिक हैं, तो पार्किंग की चिंता के अलावा भाजपा हरियाली लेकर आ रही है। नगर निगम और नगर परिषद के बीच चिंताओं का अंतर भले ही कम हो, लेकिन इन्हें दूर करने के इरादों में भारी अंतर होना चाहिए। सोलन में भाजपा उन मुद्दों को छू रही है, जो आधारभूत होने के अलावा राजनीतिक अधिक हैं। पालमपुर अपनी पृष्ठभूमि को खंगालते हुए सबसे पहले 'पर्यटन सर्किट' का ताज पहन रहा है, तो ऐसे संकल्प आर्थिक ऊर्जा पैदा करते हैं। शहर की अधोसंरचना में फ्लाईओवर, अंडरपास, पार्किंग तथा पार्कों के लिए जमीन तलाशी जा रही है। रेन शेल्टर और सोलर प्लांट लगाने के अलावा नगर निगम अपनी खुशहाली-रखवाली के लिए अपना कानून बनाना चाहती है। भाजपा का संकल्प चुनाव जीतने की पेशकश के साथ-साथ टीसीपी कानून को बाय-बाय कहना चाहता है। यानी शहरी तहजीब के फंदे उतार कर सियासी वादों का चरित्र कहीं अन्यत्र ही नाच रहा है। भाजपा के चारों संकल्प पत्रों से कहीं आगे धर्मशाला के संबोधन दर्ज हैं। सबसे अहम बिंदु यह है कि आने वाले वर्षों की जरूरत को समझा जा रहा है। भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विकास के नक्शे को उकेरा गया है। जर्जर सरकारी इमारतों को हटाते हुए डिकंजेशन के हर पहलू पर गौर हो रहा है। मेले और छिंज मैदानों का विस्तार और साइकिलिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। पुराने बाजारों-क्षेत्रों का पुनर्वास और चरान खड्ड से भागसूनाग तक फनिक्युलर ट्रैफिक व्यवस्था जैसे महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चुने जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक्टर ऑन कॉल तथा युवाओं के लिए फुटबाल अकादमी के संकल्प ऊंचे हैं। स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने के अलावा रुके कार्यों पर भाजपा ने दस्तखत किए हैं। जाहिर है संकल्प की उत्तम पद्धति अपनाने में हर शहर में भाजपा ने वादे किए हैं। दरअसल ये चारों निगम आने वाले विधानसभा चुनावों की चार दिशाएं साबित हो सकते हैं। ऐसे में पालमपुर में भाजपा का निरंतर राजनीतिक सूखा क्या इस संकल्प पत्र से हट जाएगा। मंडी का विजय घोष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जय जयकार करेगा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल सोलन को मुट्ठी बंद करके अपने प्रभाव का क्षेत्रफल बढ़ा पाएंगे या सुधीर शर्मा एक बार फिर अपने विजन की करामात से कांग्रेस को चकमा दे पाएंगे। भाजपा ने कोशिश ऐसी जरूर की है कि तमगे लौट आएं, अपना नूर दिखा कर।

> मंडी के भीतर और मंडी के बाहर दो तरह की सत्ताएं रही हैं। एक ने पिछले चुनाव के धरातल पर जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया, तो शहर के भीतर तक नगर निगम आया और दूसरे ने सांस्कृतिक विरासत ढूंढी, तो शिवधाम का मंजर नजर आया। इक्यासी मंदिरों की प्रदक्षिणा में सारे मंडी का जज्बा है, तो भाजपा ने पहली बार कसम खाई कि कुछ करके दिखाएगी। मंडी के अगल-बगल से लांघते पर्यटक को रोकना है, तो कसौटियों की बुनियाद पर मंडी को नगर निगम की सक्रियता चाहिए। अधोसंरचना निर्माण के वादे सामने आए हैं, तो याद रखना होगा कि शहर के सपनों को जिंदा रखना होता है। वर्षों पहले पंडित सुखराम ने इंदिरा मार्किट की परिकल्पना में जो एहसास शहर को दिया, क्या इस संकल्प के बाजुओं पर वैसा कोई अवतार है। बेशक कांग्रेस ने हमीरपुर और शिमला में दो बड़े व्यापारिक परिसर बनाने का संकल्प उतारा है, लेकिन देखना यह होगा कि इस स्तर की परियोजनाएं क्या सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला को मिलती हैं। सोलन में नगर निगम क्षेत्र को जो विजन भाजपा दे रही है, उसके अनुसार शहर की जलापूर्ति अब सही ढर्रे पर आएगी। सोलन के इर्द-गिर्द अब पहाडियां कम अपार्टमेंट अधिक हैं, तो पार्किंग की चिंता के अलावा भाजपा हरियाली लेकर आ रही है। नगर निगम और नगर परिषद के बीच चिंताओं का अंतर भले ही कम हो, लेकिन इन्हें दूर करने के इरादों में भारी अंतर होना चाहिए। सोलन में भाजपा उन मुद्दों को छू रही है, जो आधारभूत होने के अलावा राजनीतिक अधिक हैं।

दृष्टि कोण

बैंकिंग तंत्र में बढ़ता बट्टा खाता और फ्रॉड

बैंकिंग व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के आर्थिक ढांचे की रीढ़ मानी जाती है। यह केवल धन के लेन-देन का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों की मेहनत की कमाई, भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक विश्वास का आधार भी है। जब आम आदमी अपनी जीवनभर की बचत बैंक में जमा करता है, तो उसके पीछे केवल आर्थिक व्यवहार नहीं, बल्कि व्यवस्था पर गहरा भरोसा भी जुड़ा होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग तंत्र के सामने बढ़ते बट्टा-खाते, एनपीए और बैंकिंग फ्रॉड ने इस भरोसे को गंभीर चुनौती दी है। आरटीआई और संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से 2023 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के ऋण बट्टा खाते में डाले। यह राशि इतनी विशाल है कि इससे देश के अनेक बड़े बुनियादी ढांचा प्रकल्प खड़े किए जा सकते थे। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि इस राशि में से औसतन केवल 10 प्रतिशत के आसपास ही प्रभावी वसूली हो सकी। यद्यपि 'राइट-ऑफ' को सीधे कर्जमाफी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह बैंकिंग की तकनीकी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लंबे समय से डिफॉल्ट खातों को बैलेंस शीट से हटाया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूपीए शासनकाल में वार्षिक औसत बट्टा-खाता लगभग 34 हजार करोड़ रुपए था, जबकि हाल के वर्षों में यह औसत बढ़कर लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच गया। इसके बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने सुधार की दिशा में कुछ सकारात्मक उपलब्धियां भी हासिल की हैं। मार्च 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 14.58 प्रतिशत तक पहुंच गया था, जो सितंबर 2024 तक घटकर लगभग 3.12 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार देश का कुल सकल एनपीए अनुपात लगभग 2.5 प्रतिशत के स्तर तक आ गया है, जिसे अपेक्षाकृत संतोषजनक माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा लगभग 6.82 लाख करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है। इन सुधारों के पीछे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एनसीएलटी, डीआरटी और कठोर ऋण मानकों जैसी व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2026 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली नए अवसरों के साथ नई चुनौतियों का भी सामना कर रही है। वर्तमान में ऋण-जमा अनुपात लगभग 79 से 82 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार बैंकिंग परिसंपत्तियां अब देश की जीडीपी के लगभग 94 प्रतिशत के बराबर हो चुकी हैं। दूसरी ओर असुरक्षित ऋण बढ़कर लगभग 46.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जो कुल ऋण का लगभग 24.5 प्रतिशत हिस्सा हैं। आज बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती केवल एनपीए नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता डिजिटल फ्रॉड भी है। वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 34771 करोड़ रुपए से अधिक के बैंकिंग फ्रॉड के मामले सामने आए। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के विस्तार के साथ साइबर अपराधियों के तौर-तरीके भी अधिक आधुनिक और खतरनाक हो गए हैं। 'डिजिटल गिरफ्तारी' जैसे नए अपराधों में ठग पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराते हैं और उनसे धन वसूलते हैं। इसके अतिरिक्त एआई आधारित सिंथेटिक पहचान, फर्जी यूपीआई रिक्वेस्ट, क्यूआर कोड फ्रॉड और मनी म्यूल खातों का उपयोग बैंकिंग अपराधों को और जटिल बना रहा है। कई मामलों में लोग अनजाने में अपने बैंक खातों को अवैध धन हस्तांतरण का माध्यम बना देते हैं। यही कारण है कि आरबीआई अब एआई आधारित निगरानी प्रणाली, रियल-टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और फर्जी खातों की पहचान पर विशेष जोर दे रहा है।

पेपर लीक आरोपियों का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं : राठौड़

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने फोटो और सेल्फी के आरोपों को बताया निराधार

जोधपुर (हिंस)। पेपर लीक मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक आरोपियों का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा नेताओं के साथ लग रही फोटोज और सेल्फी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं। वे आज यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेल्फी कोई भी ले सकता है, इससे किसी का संबंध साबित नहीं होता। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में प्रदेश में कई पेपर लीक हो चुके हैं, जबकि भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाएगा। राठौड़ ने दावा किया कि इस बार के नीट पेपर लीक के तार केरल से जुड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हुए जो ट्रेनिंग और नौकरी तक कर

चुके थे। उन्होंने कहा कि नीट के विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और वे दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही दावा किया कि गहलोत के करीबी तीन लोग जेल में हैं और आगे भी कार्रवाई होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और न ही होने दिया जाएगा। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। राठौड़ ने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक के तार केरल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इस मामले में कांग्रेस नेताओं को जवाब देना चाहिए। प्रदेश सरकार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी नेतृत्व से जब भी राय मांगी जाएगी, तब भाजपा संगठन अपनी तरफ से योग्य नाम सुझाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि बेईमान के साथ फोटो खिंचवाने से कोई बेईमान नहीं हो जाता है। हम राजनीतिक जीवन में हैं, हजारों लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। कौन कैसा है? इसका पता नहीं चलता। गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक से जुड़े आरोपियों के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा फोटो आपके साथ भी होगा। कौन कैसा होता है? इसकी जानकारी नहीं होती है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा की ओर से इसको लेकर की जा रही बयानबाजी पर दिलावर ने कहा कि मेरी अगर डोटासरा के साथ फोटो है। अगर वो बेईमान हैं, तो मैं बेईमान नहीं हो जाउंगा। सुप्रीम कोर्ट के राजस्थानी भाषा को लेकर जो आदेश दिया गया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम आदेश का अध्ययन करेंगे। उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। ज्ञात रहे कि नीट यूजी के आरोपियों के मदन दिलावर के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष सरकार पर हमलावर है।

क्रिकेटर युवराज के पिता व फिल्म अभिनेता योगराज के खिलाफ मामला दर्ज

वेब सीरीज *लुक्खे* में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दावली वीडियो वायरल

चंडीगढ़ (हिंस)। अमेजन प्राइम वीडियो पर 8 मई को रिलीज हुई हिंदी वेब सीरीज *लुक्खे* के एक एपिसोड में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार की शाम मामला दर्ज कर लिया है। योगराज सिंह स्वयं भी क्रिकेटर रह चुके हैं और वह कई पंजाब व हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं एडवोकेट उज्ज्वल भसीन और जतिन वर्मा की तरफ से यह शिकायत 12 मई को एसएसपी को भेजी गई है। उन्होंने दलील दी है कि सोशल मीडिया पर 17 सेकेंड का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें महिलाओं के खिलाफ शर्मनाक, अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पत्र में दूसरा तर्क है यह न केवल अपमानजनक है, बल्कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों और पत्नियों सहित हर महिला की गरिमा, शालीनता और सम्मान पर सीधा हमला है। शिकायतकर्ताओं ने एसससपी से मांग की थी कि योगराज सिंह और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद सेक्टर 36 के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की

गई है। इस मामले में पंजाब महिला आयोग भी सख्त हो गया है। आयोग ने पंजाब पुलिस को पत्र लिखकर सीनियर अधिकारी से जांच करवाने के लिए कहा है। पंजाब राज्य महिला आयोग की ओर से गुरुवार को पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर चंडीगढ़ को एक पत्र भेजा गया, जिसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। वीडियो में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। आयोग ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए कहा है।

वर्ल्ड एब्डोमिनल कैंसर डे होगी मल्टीसिटी वॉक

जयपुर (हिंस)। वर्ल्ड एब्डोमिनल कैंसर डे के अवसर पर 17 मई को दुनियाभर के विभिन्न शहरों में कैंसर जागरूकता के लिए मल्टीसिटी वॉक आयोजित की जाएगी। जयपुर में यह वॉक जलेब चौक से निकाली जाएगी, जबकि 19 मई को होटल हॉलिडे इन में प्रिवेंटिव जीआई ऑन्कोलॉजी विषय पर विशेषज्ञों की पैनल डिस्कशन आयोजित होगी। आयोजन एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट द्वारा फोर्टिस हॉस्पिटल और आईआईईएमआर के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट के संस्थापक एवं वर्ल्ड एब्डोमिनल कैंसर डे के फाउंडर डॉ. संदीप जैन, फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. मनीष अग्रवाल, जोवा इटालिय फार्मा कंपनी के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता, जयपुर रनर्स क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक शर्मा, एडवोकेट कमलेश शर्मा, प्रो. एसएस शर्मा और आईआईईएमआर के निदेशक मुकेश मिश्रा भी उपस्थित रहे। डॉ. संदीप जैन ने कहा कि कैंसर से लड़ाई केवल इलाज से नहीं बल्कि जागरूकता से भी जीती जा सकती है। समय पर पहचान और सही उपचार से असंख्य लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि एब्डोमिनल कैंसर में पेट के भीतर होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे गैस्ट्रिक, लिवर, पैंक्रियाटिक, कोलन, गॉल ब्लैडर और किडनी कैंसर शामिल हैं। 19 मई को आयोजित पैनल डिस्कशन में देश के अग्रणी विशेषज्ञ प्रिवेंटिव जीआई ऑन्कोलॉजी और कैंसर की शुरुआती पहचान पर मंथन करेंगे। इसमें एआई एंडोस्कोपी, कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग, गॉल ब्लैडर कैंसर की रोकथाम और अल्कोहल से संबंधित लिवर सिरोसिस जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में डॉ. एसएस शर्मा, डॉ. संदीप जैन, डॉ. आरके जेनॉ, डॉ. सुधीर महाऋषि, प्रो. वीए सारस्वत सहित कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. मनीष अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नियमित जांच, शुरुआती पहचान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। वहीं मुकेश मिश्रा ने बताया कि मल्टीसिटी वॉक के जरिए लोगों को स्वस्थ रहने और कैंसर के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया जाएगा।

किसान जैविक खेती को अपनाएं, रासायनिक खाद के प्रयोग से बचें : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जालौर/जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जालोर जिले के पंसेरी गांव में सुबह की सैर कर ग्रामीणों से रामा श्यामा की तथा उनकी कुशलक्षेम पूछी। वहीं, स्कूल जा रहे छोटे बच्चों से बातचीत कर चॉकलेट और टॉफी दी और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुबह की सैर के बाद मुख्यमंत्री ने गांव की चौहटा (गांव की चौपाल का मुख्य केंद्र) पर ग्रामीणों से बातचीत की। साथ ही, उनकी विभिन्न विकास मांगों को सुनकर मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री केके विश्नोई सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद

रहे। इससे पूर्व बुधधार को मुख्यमंत्री शर्मा ने जालौर के पंसेरी में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में किसानों एवं पशुपालकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। इसी क्रम में हमारी सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान संचालित कर राज्य की प्रत्येक पंचायत के सुनियोजित विकास का ब्लू प्रिंट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली-पानी की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों की सिंचाई जरूरतों की पूर्ति के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान की है। यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर का सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ माही तथा देवास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। सोम-कमला-अंबा परियोजना के माध्यम से जवाई बांध में जल आएगा, जिससे जालौर, पाली और सिरोही के लोगों को पानी की आपूर्ति भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जिलों के किसानों को दिन के समय में बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो कि वर्ष 2027 तक प्रदेशभर में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान ड्रिप-स्पिंकलर से सिंचाई करें, जैविक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खाद का उपयोग करने से बचें।

नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग तेज : नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय बहस छेड़ने का आह्वान

जयपुर (हिंस)। नीट परीक्षा 2026 में पेपर लीक और लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के बाद अब देशभर में परीक्षा प्रणाली को लेकर विरोध तेज होने लगा है। राष्ट्रीय यूनाइटेड बैकवर्ड क्लासेज (एनयूबीसी) सहित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग उठाई है। महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित मांग पत्र में कहा कि नीट परीक्षा के दौरान लगातार पेपर आउट, तकनीकी गड़बड़ियों और अनियमितताओं ने लाखों विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को मानसिक तनाव में डाल दिया है। उनका कहना है कि बार-बार सामने आ रहे विवादों से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्रधानमंत्री की अपील को पूरी गंभीरता से पढ़कर, समझकर और चिंतन-मनन के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए : मुख्यमंत्री

लखनऊ (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान देशवासियों ने एकजुट होकर संकट का सामना किया था, पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के बीच उसी सामूहिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय भावना के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह वैश्विक संकट है, जिसका असर ईंधन, खाद्य व उर्वरक आपूर्ति पर पड़ सकता है। ऐसे समय हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विकल्पों को अपनाकर देश के आत्मनिर्भरता अभियान को मजबूती दे। मुख्यमंत्री गुरुवार को लखनऊ के होटल ताज में टाइम्स ऑफ इंडिया के *9 डिफाइनिंग इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी* कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील का उल्लेख करते हुए ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल और शटल बस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने 7700 से अधिक गोआश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देशहित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे। उन्होंने अधूरी जानकारी के आधार पर नकारात्मक टिप्पणी करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अपील को पूरी गंभीरता से पढ़कर, समझकर और चिंतन-मनन के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और देश समृद्ध होगा तो हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में आज जो आर्थिक समृद्धि दिखाई दे रही है, उसकी जड़ें मात्र 400-500 वर्ष पुरानी हैं, जबकि भारत में यह समृद्धि इससे बहुत पहले विद्यमान थी। लेकिन जब हमने अपने संसाधनों, ज्ञान और नवाचार पर विश्वास करना छोड़ दिया, रिसर्च एवं डेवलपमेंट को उपेक्षित किया तो हम पिछड़ते गए। उस समय तीर्थयात्रा पर्यटन का प्रमुख रूप थी। केदारनाथ में जलाभिषेक के लिए रामेश्वरम का जल और रामेश्वरम में अभिषेक के लिए गंगोत्री का जल ले जाने की परंपरा उत्तर और दक्षिण को जोड़ती थी। द्वादश ज्योतिर्लिंग और चार धाम पूरे देश को एक सूत्र में बांधते थे। जीवन इस तरह व्यवस्थित था कि कोई किसी पर बोझ न बने। यही कारण था कि भारत विश्व गुरु बना। हजार वर्षों के आक्रमणों, अत्याचारों और शोषण के बावजूद भारत अपने अस्तित्व और संस्कृति को बचाए रखने में सफल रहा, जो दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश बना दिया गया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, त्योहारों के समय दंगे-फसाद होते थे, गुंडागर्दी और माफिया राज था। भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार और सरकारी उदासीनता चरम पर थी। सरकार बनते ही हमने पहले एक महीने तक केवल मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शाम छह बजे से रात बारह बजे तक बैठक की। हर विभाग का प्रेजेंटेशन लिया गया और कार्ययोजना तैयार की गई। खजाना खाली था, कर्मचारियों के वेतन के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने स्पष्ट नीति बनाई कि कोई भाई-भतीजावाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं। आज उत्तर प्रदेश में विकास केवल लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। सभी 75 जनपदों और 58,000 ग्राम पंचायतों में समान विकास हो रहा है। सभी जगह एक समान बिजली पहुंच रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सख्ती से लागू है। भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी के एमएसएमई क्षेत्र के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। सब कुछ भगवान भरोसे था क्योंकि सरकार चादर तानकर सो रही थी। जब सरकार सोती है तो इंस्पेक्टर राज चलता है। कारीगर हतोत्साहित और प्रताड़ित होकर पलायन कर चुका था या जैसे-तैसे गुजारा कर रहा था। लेकिन आज प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जिनमें लगभग तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश के पास आज 75,000 एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त सुरक्षा, दूसरी शर्त लैंड बैंक और तीसरी शर्त स्पष्ट नीति है। अब यूपी में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। हमने 34 सेक्टरों के लिए अलग-अलग सेक्टोरल पॉलिसी बनाई है। अब नीति भी है, नीयत भी है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति भी।

राज्यपाल को चंडीगढ़ के धार्मिक स्थलों और पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा

चंडीगढ़ (हिंस)। शिरोमणि अकाली दल, चंडीगढ़ और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर शहर से जुड़े कई अहम जनहित मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ के अध्यक्ष चरणजीत सिंह विली ने की। बैठक के दौरान चरणजीत सिंह विली ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए चंडीगढ़ के धार्मिक संस्थानों, स्थानीय निवासियों और पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को विस्तार से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले चंडीगढ़ के गुरुद्वारों और मंदिरों को प्रशासन द्वारा भेजे जा रहे उल्लंघन नोटिसों का मुद्दा उठाया। अकाली दल ने मांग की कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को एकमुश्त नीति के तहत नियमित

किया जाए। इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम में नामित किए जाने वाले 9 पार्षदों में सिख समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग भी उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कम से कम दो नामित पार्षदों की सीटें सिख समुदाय के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को दी जा रही पेंशन बढ़ाने की मांग भी बैठक में प्रमुख मुद्दा रही। नेताओं ने कहा कि मौजूदा समय में 1000 रुपए की पेंशन राशि बहुत कम है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाया जाना चाहिए। चंडीगढ़ के पार्किंग स्थलों में अव्यवस्था और ट्रैफिक जाम का मुद्दा भी राज्यपाल के सामने रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने पार्किंग स्थलों की खराब स्थिति से संबंधित तस्वीरें भी सौंपीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में साइन बोर्डों से पंजाबी भाषा हटाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई गई। साथ ही नए बने ऑडिटोरियम का नाम बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के नाम पर रखने की मांग की गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के बाद राज्यपाल का धन्यवाद किया।

रवनीत सिंह ने अमृतसर से नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया

अमृतसर (हिंस)। अमृतसर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रवनीत सिंह ने घोषणा की कि अमृतसर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 402 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा स्टेशन पर पांच नए प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रवनीत सिंह ने अमृतसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमृतसर रेलवे स्टेशन सिर्फ एक परिवहन केंद्र नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे इस स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करेगा, जो शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत बड़े स्तर पर यार्ड रीमॉडलिंग और विस्तार कार्य किए जाएंगे। स्टेशन पर पांच अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिनमें दो उत्तरी दिशा और तीन दक्षिणी दिशा में होंगे। इसके साथ पांच नई यात्री लूप लाइनें भी बनाई जाएंगी, ताकि ट्रेनों की आवाजाही आसान हो और भीड़भाड़ कम हो सके। रवनीत सिंह ने कहा कि अमृतसर में एक नया वंदे भारत मेंटेनेंस शेड भी बनाया जाएगा, जिससे रेलवे संचालन को और मजबूती मिलेगी। स्टेशन के उत्तरी हिस्से में सात कॉमर्शियल फ्लोर के साथ आधुनिक जी+10 स्टेशन भवन बनाया जाएगा, जबकि दक्षिणी हिस्से में जी+3 स्टेशन भवन तैयार किया जाएगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के उत्तर और दक्षिण हिस्से को जोड़ने हेतु दो नए सबवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा लिफ्ट, एस्केलेटर, आधुनिक पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और कवर ड्रॉप-ऑफ जोन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसी दौरान रवनीत सिंह ने अमृतसर रेलवे स्टेशन से 14664/14663 अमृत भारत एक्सप्रेस को अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन साप्ताहिक रूप से दोनों शहरों के बीच चलेगी और पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन खासतौर पर आम यात्रियों के लिए तैयार की गई है, जिसमें आधुनिक एलएचबी कोच, सीसीटीवी निगरानी, फायर सेफ्टी सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट और बेहतर शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। रवनीत सिंह ने कहा कि वर्ष 2026-27 में पंजाब के लिए रेलवे बजट बढ़ाकर 5,673 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

अगले 5 वर्षों में बिहार में एयर कनेक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है : मुख्यमंत्री

पटना (हिंस)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दरभंगा हवाई अड्डा की सुरक्षा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर दरभंगा हवाई अड्डा परिसर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005-06 में बिहार से प्रति वर्ष हवाई यात्रा करनेवालों की संख्या मात्र 2.5 लाख के करीब थी, जो अब बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गई है। अगले 5 वर्षों में बिहार में एयर कनेक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि अगले पांच वर्षों में बिहार से 4 से 5 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर सकें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील को ध्यान में रखते हुए यहां छोटे स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हरसंभव सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर कार्यक्रमों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करें। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो उसकी रूपरेखा

छोटे स्तर पर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान को ध्यान में रखते हुए हमने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक महकमा को निर्देश दिया है कि आवश्यक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम वाहनों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की बचत होगी और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला की यह धरती भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाती है। इसी धरती पर माता जानकी का जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम यहां पधारे। यह धरती त्याग का प्रतीक है। मिथिला की परंपरा और यहां के उत्पाद का प्रसार दुनिया भर में काफी तेजी से हो रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि दुनिया जिस मखाना को सुपर फूड के नाम से जानती है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषणों में इसका जिक्र करते रहते हैं। पटना से मिथिलांचल स्थित जयनगर और निर्मली पहुंचने में पहले 10 घंटे का समय लग जाता था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिथिलांचल में कराए गए विकास कार्यों के कारण ही यहां का पूरा परिदृश्य बदल गया है। इस इलाके में बड़ी संख्या में पुल-पुलियों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। इस इलाके में रोड कनेक्टिविटी के अलावा रेल कनेक्टिविटी का काफी विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में एयर ट्रैफिक का विस्तार करना है वह चाहे एयरपोर्ट के रूप में हो, एयर स्ट्रीप के रूप में हो या हेलीपोर्ट के रूप हो। मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा और वीरपुर में एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए टेंडर हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो चुका है। मुंगेर, अजगैबीनाथ, भागलपुर तथा बेगूसराय के एयरपोर्ट को भी हर हाल में चालू कराना है। अगले सप्ताह सिविल विमानन विभाग एवं भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण बाबा विद्यापति जी के नाम पर हो इसके लिए हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। इस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का भी काम कराना है। किशनगंज जिले के पोठिया अंचल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए बिहार सरकार ने 110 एकड़ भूमि दिया है। यदि और जमीन की आवश्यकता होगी तो उसे उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यक्रम को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद संजय कुमार झा, सांसद गोपाल जी ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक संजय सरावगी एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने भी संबोधित किया।

कुछ निवेशक ने पत्रकारिता की गुणवत्ता और दायरा बढ़ाने में किया निवेश

फिल्म 'द डेविल वेअर्स प्राडा 2' पत्रकारिता की रवायत को बचाने की कहानी

नई दिल्ली

डेविड फ्रैंकल निर्देशित फिल्म 'द डेविल वेअर्स प्राडा 2' फैशन की दुनिया के बारे में नहीं बल्कि पत्रकारिता की रवायत को बचाने से जुड़ी है। 2006 की उस सुपरहिट फिल्म का सीक्वेल, जिसकी कहानी फैशन की दुनिया पर आधारित थी, लेखन, तथ्यों और लोगों तक अनकही कहानियां पहुंचाने के माध्यम की स्तुति है। फिल्म की एक किरदार, ऐंडी सैक्स इस फिल्म में एक फैशन पत्रिका, 'रनवे' में फीचर संपादक के रूप में नजर आईं। पहली फिल्म में वह मिरांडा प्रिस्टली की सहयोगी थीं, जो एक सख्त लेकिन सफल संपादक की भूमिका में थीं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निश्चित तौर पर अब कहानी वर्ष 2026 की है। डिजिटल दौर ने प्रकाशन संस्थानों की दुनिया पर व्यापक और गहरा असर डाला है। इन प्रकाशन कंपनियों के सलाहकार लागत घटाने, कर्मचारी और फीचर आदि को कम करने में लगे हुए हैं। काफी संघर्ष के बाद, सैक्स और प्रिस्टली को एक निवेशक मिल जाता है जो उस तरह की पत्रकारिता के लिए फंड देने को तैयार हैं जिसे वे करना चाहती हैं और इस तरह कहानी खुशनुमा मोड़ पर खत्म होती है।

बता दें अगस्त 2013 में, मशहूर निवेशक जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को 25 करोड़ डॉलर नकद में खरीद लिया। उन्होंने इसे डिजिटल बनाने के साथ ही इसे मुनाफे में लाने में सफलता पाई और बार-बार इसके संपादकीय रुख के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, लेकिन वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले, परंपरा तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह अखबार डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन नहीं करेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों में एक-तिहाई कटौती की गई और अखबार की संपादकीय नीति बदल गई। अन्य निवेशकों ने भी स्थानीय समाचार पत्रों को खरीदते समय यही किया यानी लागत कम करने के साथ ही कर्मचारियों में कटौती की और ब्रांड मूल्य को शून्य के स्तर पर पहुंचा दिया। हालांकि कुछ निवेशक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता की गुणवत्ता और उसके दायरे को बढ़ाने में निवेश किया जैसे कि फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप के जॉन हेनरी ने 'द बॉस्टन ग्लोब' के जरिये ऐसा किया जिसे उन्होंने 2013 में खरीदा।

न्यूज़ ब्रीफ

केंद्र ने चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर तक रोक लगाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध सितंबर तक लागू रहेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 13 मई को देरशात इस आशय की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, चीनी निर्यात नीति में बदलाव किया है। सरकार ने आईटीसी (एचएस) कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत चीनी के लिए एक्सपोर्ट नीति को प्रतिबंधित से बदलकर निषिद्ध कर दिया है। इस आदेश में कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट को शामिल किया गया है। ये रोक यूरोपीय संघ और अमेरिका को सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटे के तहत, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएस) के तहत, और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों सरकारों के शिपमेंट के जरिए किए जाने वाले चीनी निर्यात पर लागू नहीं होगी। यही नहीं, जो खेप पहले से ही निर्यात की प्रक्रिया में है, उसे भी इस रोक से छूट दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक अगर इसे सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो एक्सपोर्ट नीति वापस प्रतिबंधित श्रेणी में आ जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने पहले मिलों को 1.59 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष खपत से कम रहने की उम्मीद है। प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार कमजोर हुई है।

ईंधन की कीमतों में तेज उछाल से थोक महंगाई दर अप्रैल में 8.3 फीसदी पर

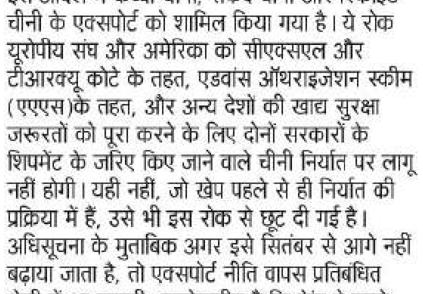

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी इजाफा हुआ है। ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण अप्रैल में थोक महंगाई दर बढ़कर 8.30 फीसदी हो गई है, जो मार्च में 3.88 फीसदी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को आंकड़ों में बताया कि ईंधन और बिजली श्रेणी में महंगाई दर अप्रैल में 24.71 फीसदी हो गई, जो मार्च में 1.05 फीसदी थी। इसके साथ ही कच्चे तेल की महंगाई दर अप्रैल में 88.06 फीसदी रही, जबकि मार्च में यह 51.5 फीसदी थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं में महंगाई दर अप्रैल में 1.98 फीसदी रही, जो मार्च में 1.90 फीसदी थी। गैर-खाद्य वस्तुओं में महंगाई दर बढ़कर अप्रैल में 12.18 फीसदी हो गई, जो पिछले महीने मार्च में 11.5 फीसदी थी। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2026 में मुद्रास्फीति खनिज तेल, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, मूल धातु, अन्य विनिर्माण और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण अधिक रही है। ईंधन और बिजली श्रेणी में एलपीजी में महंगाई दर अप्रैल में 10.92 फीसदी रही। हालांकि, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 50 फीसदी की वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक पेट्रोल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों को स्थिर रखा है, ताकि उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी के असर से बचाया जा सके। हालांकि, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई है।

अनुमतियां, लाइसेंस और अनुपालन अक्सर उद्यमियों को हतोत्साहित करते हैं

नई दिल्ली। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सालाना व्यापार सम्मेलन में भारतीय नीति निर्माण की कमी को बताया। उन्होंने कहा कि 1991 के सुधारों ने औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया लेकिन लाइसेंस राज को नहीं। कारोबारों और सरकार के बीच जुड़ाव का स्तर और साथ ही किसी उद्यम को शुरू करने और चलाने के लिए जरुरी अनुमतियां, लाइसेंस और अनुपालन आदि अक्सर उद्यमियों को हतोत्साहित करते हैं। सरकार इस मोर्चे पर काम कर रही है। उसने हजारों अनुपालन जरुरतों को समाप्त कर दिया है और बड़ी संख्या में प्रावधानों को अपराधमुक्त किया है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना है। यह मानना होगा कि वैश्विक कारोबारी माहौल बीते कुछ सालों में बदला है और भारत जैसे देश को अपने कारोबारी माहौल में सक्रिय बदलाव लाना होगा। भारत चालू खाते के घाटे में है जो बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन उसकी भरपाई के लिए टिकाऊ रूप से विदेशी मुद्रा की आवक की जरुरत होगी। मौजूदा समय में जब देश से पूंजी बाहर जा रही है तब इस जरुरत को विशेष रूप से महसूस किया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों ने संकेत दिया कि चालू वर्ष लगातार ऐसा तीसरा वर्ष हो सकता है जब भुगतान संतुलन में घाटा दर्ज होगा। पश्चिम एशिया संकट वर्तमान में पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर रहा है और शुद्ध स्तर पर भारत कुछ समय से कमजोर प्रवाह देख रहा है। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम निश्चित रूप से अल्पकालिक राहत देगा ।

समय के साथ भारत ने आईएलओ के 47 समझौतों और एक प्रोटोकॉल को किया मंजूर

नई दिल्ली

कर्नाटक ने 2023 में कारखाना श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दी तब ट्रेड यूनियनों ने जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में तर्क दिया कि यह बदलाव भारत की उस प्रतिबद्धता का उल्लंघन है जो उसने आईएलओ के काम के घंटे समझौते 1919 के तहत जताई थी। इसके तहत श्रमिकों को अधिकतम प्रतिदिन आठ घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करने का प्रावधान है। इस प्रकार जो बहस घरेलू स्तर पर उत्पादकता, वेतन और श्रमिकों की पसंद के बीच संतुलन पर होनी चाहिए थी वह एक अंतरराष्ट्रीय मामले में बदल गई।

यह अपनी तरह की कोई इकलौती घटना नहीं है। यह एक सदी पहले लिए गए फैसला का परिणाम है। भारत ने काम के घंटों को लेकर खुद को आईएलओ के नियमों के सबसे हस्तक्षेपकारी हिस्से से आबद्ध कर लिया था। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और वह 1922 से ही उसकी संचालन संस्था का स्थायी सदस्य रहा है। समय के साथ हमने आईएलओ के 47 समझौतों और एक प्रोटोकॉल को मंजूर किया। इनमें से 39 अभी तक जारी हैं।

यह समस्या उतनी गंभीर नहीं होती यदि यह समझौता सार्वभौमिक सहमति को दर्शाता। आईएलओ के 187 सदस्य देशों में से केवल 52 ने सी001 को अनुमोदित किया है और केवल 30 ने इसके साथ जुड़े काम के घंटे समझौते, 1930 (सी030) को अनुमोदित किया है। प्रमुख विनिर्माण शक्तियों जैसे अमेरिका, जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने सी001 को अनुमोदित नहीं किया है। वहीं न्यूजीलैंड ने विपरीत रास्ता अपनाया। कई दशकों तक इस संधि का पालन करने के बाद उसने इसे नामंजूर कर दिया और अब कार्य समय को राष्ट्रीय कानून और सामूहिक सौदेबाजी के जरिए नियंत्रित करता है।

भारत एक बड़ा, औद्योगीकरण की प्रक्रिया में शामिल श्रम-संपन्न अर्थतंत्र है जिसने स्वयं को 1919 के युग की कार्य समय संधि के अधीन कर लिया है, जिसे इसके अधिकांश निर्यात प्रतिस्पर्धियों ने टाल दिया है। केवल कार्य समय ही नहीं, बल्कि भारत ने अपनी 47 अनुमोदित संधियों के साथ अन्य बड़े विनिर्माण देशों की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रियता दिखाई है। जैसे अमेरिका ने 14 और चीन ने 28 को ही किया है। भारत के संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है। आईएलओ की संधियां केवल सिफारिशें नहीं हैं। आईएलओ का प्रत्यक्ष शिकायत तंत्र और त्रिपक्षीय स्वरूप उसको संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं से अलग बनाता है। किसी भी नियोक्ता या श्रमिक संगठन, किसी अन्य सदस्य राज्य, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के किसी प्रतिनिधि, या आईएलओ की अपनी संचालन संस्था द्वारा शिकायत या प्रस्तुति दर्ज की जा सकती है। गंभीर और लगातार मामलों में यह एक आयोगीय जांच का रूप ले सकता है। यदि कोई सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सहमत नहीं होती, तो आईएलओ की संचालन संस्था अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को 'ऐसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है जिसे वह उचित और आवश्यक समझे।' आईएलओ के फैसले व्यापार और सहायता की शर्तों में भी शामिल होते हैं। विशेषकर यूरोपीय संघ के साथ और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं।

सरकार ने बढ़ाया धान का एमएसपी

अब 2,441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा समर्थन मूल्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति का फैसला

किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपये भुगतान का अनुमान

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब सामान्य धान का एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ए-ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। नई दरें खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के दौरान लागू होंगी, जिसकी शुरुआत सितंबर-अक्टूबर से होगी। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी लागत का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का एमएसपी उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक रखा गया है, ताकि किसानों को बेहतर आमदनी मिल सके और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद किसानों को अनुमानित रूप से 2.60 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने आगामी सीजन में करीब 824.41 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है।

क्या है एमएसपी- धान देश की प्रमुख खरीफ फसलों में शामिल है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। एमएसपी वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है, ताकि बाजार में कीमतें गिरने की स्थिति में किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिलेगी, हालांकि बढ़ती उत्पादन लागत और महंगाई को देखते हुए कुछ किसान संगठनों ने अधिक वृद्धि की मांग भी की थी।

मुंबई में सीएनजी हुई महंगी, 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत एमएमआर में सीएनजी 84 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। अभी तक सीएनजी की कीमत 82 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से गैस की बढ़ती वैश्विक कीमतों और पश्चिम एशिया में अशांति से जुड़े करेंसी में उतार-चढ़ाव के कारण हुई है। एक बयान में कंपनी ने कहा कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाली भू-राजनीतिक बाधाओं, साथ ही गैस के महंगे सोर्सेज पर बढ़ती निर्भरता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कुल मिलाकर रुपए में गिरावट के कारण, गैस खरीद की लागत में काफी वृद्धि हुई है। सीएनजी महंगी होने के कारण ऑटो-रिक्शा यूनियनों ने किराया बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। इन यूनियनों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से ड्राइवरों की इनकम पर असर पड़ रहा है। ऑटो यूनियनों ने बेस किराए में कम से कम 1 रुपए बढ़ोतरी की मांग रखी है। एमएमआर में करीब 1.28 मिलियन वाहन सीएनजी पर चलते हैं, जिनमें करीब आधा मिलियन ऑटो और 160,000 से ज्यादा टैक्सियां चलती हैं। रिक्शा चालकों के लिए, सीएनजी महंगी होने का मतलब है कि अब ऑटो चलाने का खर्च 18 रुपए प्रति किलोमीटर से अधिक हो गया है।

गोल्ड मार्केट में चीन सबसे बड़ी ताकत अप्रैल 2026 में 8 टन सोना खरीदा

चीन सोना खरीदकर अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता करना चाहता है कम

नई दिल्ली

चीन इन दिनों दुनिया भर के गोल्ड मार्केट में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है और अप्रैल 2026 तक यह सिलसिला जारी रहा। अब इस खरीदारी ने ग्लोबल मार्केट और डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2026 में अकेले 8 टन सोना खरीदा। इसके साथ ही चीन के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर 7 करोड़ 28 लाख ट्रॉय औंस तक पहुंच गए हैं। मार्च के आखिर तक इन रिजर्व की कुल कीमत करीब 342.76 अरब डॉलर आंकी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह खरीदारी सिर्फ सामान्य निवेश नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबी आर्थिक और रणनीतिक सोच है। चीन लगातार अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। यही वजह है कि वह विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अब सोने में बदल रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन के

बीच बढ़ते तनाव, प्रतिबंधों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने बीजिंग को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर किया है। चीन मानता है कि सोना ऐसा एसेट है, जिसे कोई देश फ्रीज नहीं कर सकता यानी अगर भविष्य में आर्थिक प्रतिबंध या वैश्विक संकट बढ़ते हैं, तो सोना उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक एक और बड़ी वजह चीन की अपनी मुद्रा युआन को मजबूत बनाना भी मानी जा रही है। चीन चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जगह युआन का इस्तेमाल बढ़े। ऐसे में मजबूत गोल्ड रिजर्व उसकी वित्तीय साख बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद चीन लगातार खरीदारी कर रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बीजिंग शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन फिलहाल बाजार को हिलाने के लिए नहीं, बल्कि धीरे-धीरे एक मजबूत और सुरक्षित रिजर्व तैयार करने के मिशन पर है ।

आरबीआई दे सकता है रिकॉर्ड डिविडेंड , मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार को बड़ी राहत की उम्मीद

केंद्र को इस बार पिछले साल से भी अधिक सरप्लस मिलने की संभावना

सरकारी बैंकों के रिकॉर्ड मुनाफे से बढ़ी उम्मीदें

नई दिल्ली

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस वर्ष केंद्र सरकार को अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने की तैयारी में है। मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक तेल बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच यह रकम सरकार के लिए बड़ा वित्तीय सहारा साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई बोर्ड की इस महीने होने वाली बैठक में सरकार को दिए जाने वाले डिविडेंड और सरप्लस ट्रांसफर की अंतिम राशि पर फैसला लिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड दिया

था, जो उससे पिछले वर्ष के 2.11 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 27 प्रतिशत अधिक था। अब संभावना जताई जा रही है कि इस बार यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है।

आरबीआई द्वारा सरकार को दिया जाने वाला सरप्लस 'इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क' के तहत तय किया जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार रिजर्व बैंक को अपनी बैलेंस शीट में कंटीजेंट रिस्क बफर (सीआरबी) को 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच बनाए रखना होता है। इसी आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि बैंक सरकार को कितनी अतिरिक्त राशि ट्रांसफर कर सकता है। केंद्र सरकार के बजट दस्तावेजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार को आरबीआई, सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कुल 3.16 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड और सरप्लस के रूप में मिलने की उम्मीद है। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3.75 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि वास्तविक राशि बजट अनुमान से ज्यादा हो सकती है।

इस उम्मीद की बड़ी वजह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मजबूत प्रदर्शन है। सरकारी बैंकों ने वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर एसेट क्वालिटी, कर्ज वितरण में तेजी और बढ़ती आय के चलते इन बैंकों का कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 11.1 प्रतिशत बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह लगातार चौथा वर्ष है जब सरकारी बैंकों ने सामूहिक रूप से लाभ दर्ज किया है।

बजट अनुमान के मुताबिक, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य निवेशों से सरकार को 75 हजार करोड़ रुपये डिविडेंड मिलने की संभावना है। वहीं कुल नॉन-टैक्स रेवेन्यू 6.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरबीआई इस बार रिकॉर्ड डिविडेंड देता है तो इससे सरकार को राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक दबावों से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी।

एस्टन विला के खिलाफ मोहम्मद सलाह की वापसी तय, कुछ मिनट ही खेल पाएंगे : आर्ने स्लाट

लंदन

लिवरपूल के स्टार फारवर्ड मोहम्मद सलाह एस्टन विला के खिलाफ होने वाले प्रीमियर लीग मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। टीम के मुख्य कोच आर्ने स्लाट ने गुरुवार को पुष्टि की कि शुक्रवार को एस्टन विला के खिलाफ मैच के लिए मोहम्मद सलाह उपलब्ध रहेंगे, लेकिन वह केवल कुछ मिनट ही खेल पाएंगे।

उम्मीद है कि वह मैदान पर उतरेंगे। स्लाट ने टीम के अन्य खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि गोलकीपर एलिसन बेकर ने टीम के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है, लेकिन उनके खेलने पर अंतिम फैसला मैच से पहले लिया जाएगा। वहीं फ्लोरियन विर्ट्ज पेट के संक्रमण से जूझ रहे हैं और एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं।

अपने भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर स्लाट ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगले सीजन भी लिवरपूल का मैनेजर रहूंगा। मेरा क्लब के साथ अनुबंध है और क्लब के साथ हमारी बातचीत सकारात्मक रही है। जब आप लीग नहीं जीतते तो आलोचना होना स्वाभाविक है और हमें इसे स्वीकार करना होगा।

मोहम्मद सलाह पिछले महीने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ मुकाबले में हैमस्ट्रिंग चोट के कारण मैदान से बाहर हो गए थे। इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि उनका सीजन खत्म हो सकता है और संभवतः लिवरपूल के लिए उनका करियर भी समाप्ति की ओर है, क्योंकि मिस्र के स्टार खिलाड़ी के सीजन के अंत में क्लब छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि, बाद में क्लब ने स्पष्ट किया था कि उनकी चोट उतनी गंभीर नहीं है जितनी शुरुआत में आशंका जताई गई थी।

प्रीमियर लीग अंक तालिका में लिवरपूल और एस्टन विला दोनों 59 अंकों के साथ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। लिवरपूल यदि यह मुकाबला जीतता है, तो अगले सीजन के यूएफा चैंपियंस लीग में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकता है।

हालांकि, इस सीजन में लिवरपूल उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया और टीम किसी भी बड़े खिताब से दूर रही। पिछले सीजन की सफलता को दोहराने में असफल रहने के बाद कोच आर्ने स्लाट के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लिवरपूल का इस सीजन का अंतिम लीग मुकाबला 24 मई को ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ खेला जाएगा।

न्यूज़ ब्रीफ

आईपीएल 2026 : ऑरेंज कैप रेस में विराट कोहली तीसरे स्थान पर पहुंचे, पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर शीर्ष पर बरकरार

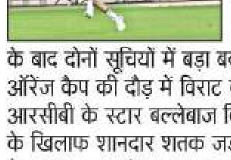

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस लगातार रोमांचक होती जा रही है। रायपुर में खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मुकाबले के बाद दोनों सूचियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऑरेंज कैप की दौड़ में विराट कोहली की बड़ी छलांग आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ शानदार शतक जड़ते हुए टीम को 193 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाया। इस पारी के साथ कोहली ऑरेंज कैप की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली ने इस सीजन 12 पारियों में 165.75 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए हैं। उनसे आगे सिर्फ गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन (501 रन) और सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन (508 रन) हैं। ऑरेंज कैप की दौड़ में इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा 481 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल 477 रन बनाकर पांचवें स्थान पर मौजूद हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 467 रन के साथ छठे नंबर पर हैं। पर्पल कैप में भुवनेश्वर कुमार नंबर-1 गेंदबाजों की सूची में आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप की दौड़ में बढ़त बना ली है। केकेआर के खिलाफ उन्होंने 1 विकेट हासिल किया, जिसके बाद उनके कुल विकेट 22 हो गए हैं। भुवनेश्वर ने इस प्रदर्शन के साथ गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 21 विकेट हैं। पर्पल कैप की सूची में चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज 19 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव, गुजरात टाइटंस के राशिद खान, कोलकाता नाइट राइडर्स के कार्तिक त्यागी और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा के नाम 16-16 विकेट दर्ज हैं।

एंड्रयू फ्लिंटाफ बन सकते हैं सिडनी थंडर के नए मुख्य कोच, जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) फ्रेंचाइजी सिडनी थंडर जल्द ही इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज आलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटाफ को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त कर सकती है। आस्ट्रेलियाई खेल वेबसाइट कोड स्पोर्ट्स के अनुसार फ्लिंटाफ इस पद की दौड़ में सबसे आगे रहे और अब उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। सिडनी थंडर पिछले कोच ट्रेवर बेलिस से अलग होने के बाद नए मुख्य कोच की तलाश में थी। इंग्लैंड को 2019 वनडे विश्व कप जिताने वाले बेलिस ने पांच वर्षों तक टीम का मार्गदर्शन किया था। उनके कार्यकाल में टीम 2024-25 सीजन के फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन 2023-24 और 2025-26 सीजन में सिडनी थंडर अंतिम स्थान पर रही। ट्रेंट कोपलैंड, जो सिडनी थंडर के महाप्रबंधक हैं, ने बेलिस के जाने के बाद कहा था कि टीम विश्वस्तरीय टी20 कोच की तलाश कर रही है और अब फ्लिंटाफ के रूप में टीम को बड़ा नाम मिलने जा रहा है। एंड्रयू फ्लिंटाफ पिछले एक साल से इंग्लैंड लायंस टीम के कोच के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आस्ट्रेलिया दौरे पर इंग्लैंड लायंस टीम का नेतृत्व भी किया था। इसके अलावा फ्लिंटाफ इंग्लैंड की सीमित ओवर टीम के साथ सलाहकार की भूमिका भी निभा चुके हैं।

अमेरिकी दिग्गज वीनस विलियम्स 45 साल की उम्र में करेंगी फ्रेंच ओपन में वापसी, हेली बैपटिस्ट के साथ खेलेंगी महिला युगल

नई दिल्ली। अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स एक बार फिर ग्रैंड स्लैम कोर्ट पर नजर आएंगी। 45 वर्षीय वीनस इस महीने शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन 2026 में महिला युगल मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। वह युवा अमेरिकी खिलाड़ी हेली बैपटिस्ट के साथ जोड़ी बनाकर खेलेंगी, जो उनसे 21 साल छोटी हैं। फ्रेंच ओपन आयोजकों ने बुधवार को महिला युगल स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें वीनस विलियम्स और हेली बैपटिस्ट की जोड़ी भी शामिल है। रोलां गैरां में होने वाला यह प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टूर्नामेंट 24 मई से शुरू होगा। हालांकि वीनस इस बार महिला एकल वर्ग में हिस्सा नहीं लेंगी। वीनस विलियम्स ने इस साल आस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड के जरिए वापसी की थी, जहां वह पहले दौर में हार गई थीं। इसके साथ ही वह आस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी भी बनी थीं।

सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में पीडब्ल्यूएल सितारों का दबदबा, भारतीय कुश्ती को मिला नया मजबूती भरा मंच

नई दिल्ली/गोंडा

प्रो रेसलिंग लीग (पीडब्ल्यूएल) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह भारतीय कुश्ती के विकास और प्रतिभाओं को निखारने का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। 10 से 12 मई 2026 तक गोंडा में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में पीडब्ल्यूएल सीजन-5 में हिस्सा लेने वाले कई पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए और आगामी विश्व चैंपियनशिप तथा कामनवेल्थ चैंपियनशिप के चयन ट्रायल्स के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की।

टूर्नामेंट में पीडब्ल्यूएल से जुड़े पहलवानों का दबदबा देखने को मिला, जिसने यह स्पष्ट किया कि लीग भारतीय पहलवानों को उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान कर उन्हें बड़े मंचों के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है।

पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में यूपी डामिनेटर्स के सागर ने 57 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं महाराष्ट्र केसरी के यश तुषीर ने 74 किग्रा वर्ग में बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

यश तुषीर की जीत विशेष रूप से प्रेरणादायक रही। पूर्व विश्व जूनियर कांस्य पदक विजेता तुषीर पिछले दो वर्षों से गंभीर चोटों से जूझ रहे थे। घुटने, कंधे और पैर की उंगली की चोटों के कारण उन्हें लंबे समय तक पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हालांकि, गोंडा में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार पांच मुकाबले जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया और यह संकेत दिया कि वह फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं।

टाइगर्स आफ मुंबई दंगल्स के नवीन ने 79 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारतीय कुश्ती के स्टार पहलवान दीपक पूनिया ने 92 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि जोड़ दी। दीपक ने पीडब्ल्यूएल सीजन-5 में महाराष्ट्र केसरी का प्रतिनिधित्व किया था।

महिला वर्ग में दिल्ली दंगल वारियर्स की अंजलि ने 62 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया और राष्ट्रीय टीम चयन की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत की।

इन उपलब्धियों ने एक बार फिर यह साबित किया कि पीडब्ल्यूएल भारतीय पहलवानों को दबाव भरे मुकाबलों में खुद को साबित करने और विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का प्रभावी मंच प्रदान कर रही है।

पीडब्ल्यूएल के सीईओ और प्रमोटर अखिल गुप्ता ने कहा कि लीग का उद्देश्य भारतीय कुश्ती को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सितारों, ओलंपियन और देश के उभरते पहलवानों को एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा का अवसर देकर पीडब्ल्यूएल देश में मजबूत कुश्ती इकोसिस्टम तैयार कर रही है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित पीडब्ल्यूएल सीजन-5 में छह फ्रेंचाइजी टीमों — टाइगर्स आफ मुंबई दंगल्स, हरियाणा थंडर्स, महाराष्ट्र केसरी, यूपी डामिनेटर्स, पंजाब रायल्स और दिल्ली दंगल वारियर्स — ने हिस्सा लिया था। इस सीजन में हरियाणा थंडर्स ने खिताब अपने नाम किया था।

पीडब्ल्यूएल का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत द्वारा जीते गए 17 पदकों में से 11 पदक पीडब्ल्यूएल से जुड़े पहलवानों ने हासिल किए, जो यह दर्शाता है कि यह लीग भारतीय कुश्ती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

थाईलैंड ओपन : पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में, सात्विक-चिराग की जोड़ी भी आगे बढ़ी

बैंकाक

भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और टूर्नामेंट की छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने महिला एकल के दूसरे दौर में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को सीधे गेमों में 21-13, 21-15 से हराया। सिंधु ने यह मुकाबला महज 28 मिनट में अपने नाम किया।

अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व नंबर-3 अकाने यामागुची से होगा, जहां भारतीय स्टार के सामने कड़ी चुनौती रहने वाली है।

पुरुष एकल वर्ग में सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने चीन के झू शुआन चेन को 21-12, 21-13 से हराकर अंतिम-8 में प्रवेश किया। 39 मिनट तक चले इस मुकाबले में लक्ष्य ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया।

क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के ली चिया हाओ और थाईलैंड के दूसरी वरीयता प्राप्त कुनलावुत वितिदसर्न के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

पुरुष युगल में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया की ब्रायन जेरेमी गूंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विश्व नंबर-4 भारतीय जोड़ी ने यह मुकाबला 44 मिनट में जीता।

अब अगले दौर में सात्विक-चिराग का सामना जापान की छठी वरीयता प्राप्त ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जोड़ी से होगा।

हालांकि, युवा भारतीय खिलाड़ी देविका सिहाग का अभियान दूसरे दौर में समाप्त हो गया। इस साल थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 खिताब जीतने वाली देविका को मेजबान थाईलैंड की पिचामोन ओपाटनिपुथ ने 23-21, 21-11 से हराया।

दिन में आगे भारत के पूर्व विश्व नंबर-1 किदांबी श्रीकांत भी चीनी ताइपे के सू ली यांग के खिलाफ अपने दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे।

दिल्ली को ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बनाने पर चर्चा, कपिल देव ने दिया सहयोग का भरोसा

नई दिल्ली। भारत के महान क्रिकेटर और प्रोफेशनल गोल्फ टूर आफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू से मुलाकात की। इस दौरान राजधानी दिल्ली को विश्वस्तरीय ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने में गोल्फ की संभावित भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पीजीटीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमनदीप जोहल भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की उन योजनाओं और पहलों का जिक्र किया, जिनका उद्देश्य राजधानी की अंतरराष्ट्रीय पहचान और वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करना है। उन्होंने इस दिशा में कपिल देव से सहयोग की अपील भी की। कपिल देव ने कहा कि दिल्ली में गोल्फ के विकास के लिए मजबूत आधार पहले से मौजूद है और वह ऐसे किसी भी प्रयास में अपना समय और सहयोग देने के लिए तैयार हैं, जो राजधानी की वैश्विक छवि को बेहतर बनाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि खेल किसी भी शहर की अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

ईस्ट ज़ोन इंटर स्कूल ओपन कराटे प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को किया गया सम्मानित

वाराणसी

ईस्ट ज़ोन इंटर स्कूल ओपन कराटे प्रतियोगिता 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कानिनजुकु आरबी मार्शल आर्ट्स अकादमी की ओर से गुरुवार को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डा. प्रभाकर शर्मा तथा असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कुमार ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 13 मई तक संत अतुलानंद कान्वेंट स्कूल, कोइराजपुर वाराणसी में किया गया था।

सम्मानित खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक विजेता शिवाक्षी त्रिगुण, अधीता वर्मा, अद्रिजा उपाध्याय, आर्याही सहगल, शिवेश शर्मा, आयुष राय, आरुषि वर्मा, अनुष्का कुमारी और आरुष देव वर्मा शामिल रहे। रजत पदक विजेताओं में अदिति अहेरवार और सताक्षी त्रिगुण को सम्मानित किया गया। कांस्य पदक विजेता अरिंदम उपाध्याय और राघव त्रिपाठी को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर टीम कोच अदिति सोनकर भी मौजूद रहीं। सम्मान समारोह में खिलाड़ियों के अभिभावकों, प्रशिक्षकों तथा अन्य खिलाड़ियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और उपलब्धियों की सराहना की गई। अकादमी के कोच अरविंद कुमार यादव ने कहा कि खेल बच्चों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। कराटे जैसे खेल बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक मजबूती विकसित करते हैं। साथ ही खेल भावना के जरिए बच्चों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास भी होता है। खिलाड़ियों की यह सफलता निरंतर अभ्यास, समर्पण और सकारात्मक सोच का परिणाम है, जो अन्य बच्चों को भी खेलों के प्रति प्रेरित करेगी।

भारतीय जूनियर पुरुष हाकी टीम के नए कोच बने फ्रेडरिक सोयेज

नई दिल्ली

हाकी इंडिया ने गुरुवार को फ्रांस के अनुभवी कोच फ्रेडरिक सोयेज को भारतीय जूनियर पुरुष हाकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारत के 2036 ओलंपिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मजबूत और दीर्घकालिक हाई-परफार्मेंस ढांचा तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

यूरोपीय हाकी के सबसे अनुभवी और सफल कोचों में गिने जाने वाले फ्रेडरिक सोयेज के पास तीन दशक से अधिक का अनुभव है। वह 15 वर्षों तक फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, जबकि पिछले 15 वर्षों से विश्व स्तरीय हाकी टीमों के मुख्य कोच के रूप में काम कर चुके हैं।

फ्रेडरिक सोयेज ने 1995 से 2010 तक फ्रांस के लिए खेलते हुए 196 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 195 गोल दागे। इसके बाद उन्होंने फ्रांस और स्पेन की राष्ट्रीय पुरुष हाकी टीमों को कोचिंग दी। वह तीन ओलंपिक खेलों का अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने स्पेन टीम को रियो 2016 और टोक्यो 2020 ओलंपिक में मार्गदर्शन दिया, जबकि पेरिस 2024 ओलंपिक में फ्रांस टीम के मुख्य कोच रहे।

उनकी कोचिंग में स्पेन ने 2019 यूरोपीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इसके अलावा टीम ने रियो और टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया।

युवा खिलाड़ियों को निखारने में भी सोयेज का रिकार्ड शानदार रहा है। उन्होंने 2013 में दिल्ली में आयोजित एफआईएच जूनियर पुरुष हाकी विश्व कप में फ्रांस को ऐतिहासिक रजत पदक दिलाया था। हाल ही में उन्होंने 2025 यूरोपीय चैंपियनशिप में फ्रांस की अंडर-18 पुरुष टीम को भी रजत पदक तक पहुंचाया।

सोयेज 2021 से 2024 तक फ्रेंच हाकी फेडरेशन के हाई-परफार्मेंस निदेशक भी रहे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के विकास और प्रदर्शन प्रणाली की जिम्मेदारी संभाली।

उनके कोचिंग करियर में दो एफआईएच पुरुष हाकी विश्व कप (2018 और 2023) तथा छह यूरोपीय चैंपियनशिप शामिल हैं। घरेलू स्तर पर उन्होंने लिले एमएचसी क्लब को 2012 में फ्रेंच इंडोर और आउटडोर चैंपियनशिप खिताब भी दिलाए।

फ्रेडरिक सोयेज को हाई-परफार्मेंस सिस्टम, खिलाड़ी विकास और पेनल्टी कार्नर रणनीति के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनकी टीमों की खास पहचान मजबूत रणनीति और निरंतर प्रदर्शन रही है।

हाकी इंडिया अध्यक्ष डा. दिलीप तिर्की ने कहा, हम फ्रेडरिक सोयेज का हाकी इंडिया परिवार में स्वागत करते हैं। उनके पास ओलंपिक, विश्व कप और यूरोपीय चैंपियनशिप का व्यापक अनुभव है। हमें विश्वास है कि उनका अनुभव भारतीय हाकी को 2036 ओलंपिक के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में मजबूती देगा।

उन्होंने आगे कहा कि हाकी इंडिया का उद्देश्य सिर्फ तत्काल परिणाम हासिल करना नहीं, बल्कि सब-जूनियर से लेकर सीनियर स्तर तक एक मजबूत और एकीकृत कोचिंग संरचना तैयार करना है। हाकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत विकास प्रणाली तैयार करना है। फ्रेडरिक सोयेज का अनुभव भारतीय जूनियर हाकी कार्यक्रम को नई दिशा देगा और भविष्य के लिए मजबूत प्रतिभा तैयार करने में मदद करेगा।

जहां लोग करते हैं रिश्वत से सख्त नफरत

दुनियाभर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रिश्वत लेने से जरा भी कुरेज नहीं करते। पैसे की ललक लोगों में इस कद्र बढ़ गई है कि रिश्वत लेनी या देनी आम बात हो गई है लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी हैं जहां लोग रिश्वत से सख्त नफरत करते हैं। जी हां, बेलारूस एक ऐसी जगह है जहां पर लोग रिश्वत से दूर रहते हैं। बेलारूस का अर्थ होता है, व्हाइट रशिया (सफेद रूस)। ईस्टर्न यूरोप में स्थित बेलारूस, पॉलैंड और रूस के बीच है। यहां के लोग बहुत सारी चीजों के लिए रूस पर निर्भर हैं। वह आर्थिक और रोजगार संसाधनों से ज्यादा अहमियत अपनी सोच, एजुकेशन और सिद्धांतों के देते हैं। यहां के नागरिक नियमों की कड़ी पालना करते हैं। पुलिस अधिकारी रिश्वत नहीं लेते हैं। 16 साल की उम्र में ही लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यहां ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जो बेलारूसियन भाषा का कोर्स कराती हो या इसका प्रशिक्षण देती हो।

विटामिन बी-3 खाओ,बढ़ती उम्र की चिंता भगाओ

खुशी की खबर है कि यदि विटामिन बी-3 और उसकी उपलब्धता वाले तत्वों का सेवन करें तो आयु बढ़ने के कारण शरीर में आने वाले परिवर्तनों पर थोड़ा विराम लग सकता है और उम्र से जुड़े मधुमेह जैसे रोग भी जल्द नहीं घेर पाएंगे। मैड्रिड के आईएमडीईए फूड के वैज्ञानिकों ने एक या कुछ ऑक्सीकरण रोधी एंजाइमों की बजाय कोशिकाओं की समूची ऑक्सीकरण रोधी क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया है।

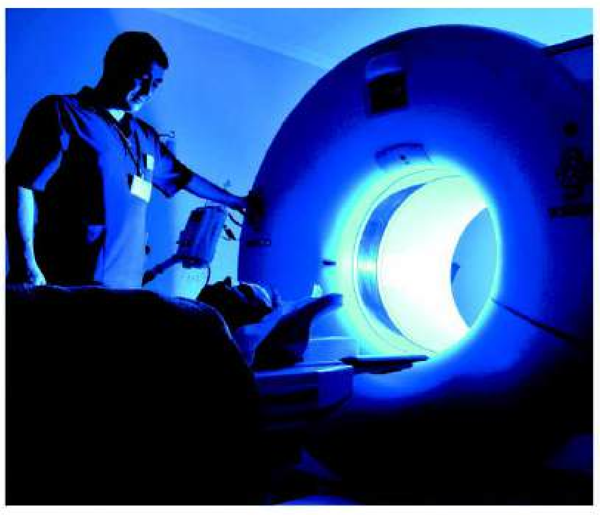

अल्जाइमर से भूली बातें वापस आ सकती हैं याद

अल्जाइमर के कारण लोग बातें भूल जाते हैं। उन्हें याद दिलाना जटिल काम है। लेकिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सुसुमु तोनेगावा ने अपने नए शोध के आधार पर पाया है कि दिमाग के एक खास हिस्से में नीली रोशनी डालने से याददाश्त वापस लाई जा सकती है। जापानी वैज्ञानिक सुसुमु को जेनेटिक मैकेनिज्म में उनकी खोज के लिए 1987 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे मोल्येकुलर (आणविक) जीवविज्ञानी हैं। लेकिन उन्हें इम्यूनोलॉजी (रोगक्षमता विज्ञान) में काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब वे न्यूरोसाइंस (तंत्रिका विज्ञान) के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुसुमु की टीम ने अभी चूहे तक ही प्रयोग किया है और वे सफल रहे हैं।

उनका कहना है कि याददाश्त के मामले में चूहे और आदमी में एक समान चीजें पाई जाती हैं इसलिए यह संभावना बनी है। अल्जाइमर के शुरुआती स्टेज में तो इसकी संभावना ज्यादा है कि याददाश्त वापस लाई जाए। इस प्रयोग के बारे में 'नेचर' जर्नल में इस टीम का लेख छपा है।

कैसे किया

इसके लिए चूहे में जेनेटिक बदलाव लाया गया ताकि उसके दिमाग में उस तरह की स्थिति लाई जा सके जो अल्जाइमर की शुरुआत में होती है। ऐसे कई चूहों को एक बक्से में रखा गया जिसके पेंदे में काफी कम स्तर का बिजली का करेंट दिया गया। यह उनके लिए असुविधाजनक तो था लेकिन खतरनाक नहीं था। इसका मकसद उनके पैरों को शॉक ट्रीटमेंट देना था। थोड़े दिनों बाद दिमाग की स्कैनिंग से लगा कि वे कुछ बातें भूल गए हो सकते हैं। फिर, उन चूहों के सिर के एक खास हिस्से को लेजर से नीली रोशनी डालकर उत्तेजित किया गया। इस हिस्से को 'एनग्राम सेल्स' कहते हैं। इससे उन्हें उस शॉक की याद आने लगी।

क्या संभावनाएं हैं

सामान्य चूहे पर भी इसी तरह के प्रयोग किए गए। इसका मकसद यह देखना था कि उनके दिमाग पर वही असर होता है या वे सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं। सामान्य तरीके का व्यवहार पाए जाने के बाद यह पाया गया कि अल्जाइमर का इस तरह इलाज किया जाना संभव है। चूंकि इसमें ऑप्टिकल (प्रकाशीय) तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए इसे ऑप्टोजेनेटिक्स नाम दिया गया है। आने वाले दिनों में इस तरह के प्रयोग लोगों पर भी किए जाएंगे।

डिप्रेशन से डरें नहीं

जिंदगी हमें तरह-तरह के रंग दिखाती है। इसमें हमें कभी खुशियों की सौगात मिलती है, तो कभी दुख का अहसास भी होता है। कई बार हमारे जीवन का दुख काफी लंबा हो जाता है जो, डिप्रेशन यानी अवसाद का कारण बन सकता है। यह जीवन पर पडने वाला ऐसा काला साया है, जिससे जीवन के प्रति रुचि खत्म होने लगती है और दिन-प्रतिदिन के कामकाज से भी मन उचट जाता है, लेकिन अब इस मनोरोग से छुटकारा संभव है...

डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ी कई बातें भी डिप्रेशन केलिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे हमारे जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव जिसमें किसी प्रियजन का बिछड़ना, नौकरी का छूट जाना, विवाह संबंधों में टूटन, शिक्षा के क्षेत्र में असफलता और इस तरह की अन्य समस्याएं अवसाद का कारण बनती हैं। इसके अलावा जीवन के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अवसाद या डिप्रेशन से कहीं ज्यादा ग्रस्त होते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि मैं सफल नहीं होऊंगा, इसलिए यह कार्य नहीं कर सकता या फिर कई लोगों के मन में हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी का डर बना रहता है जिससे उनके अवसाद में जाने का खतरा बना रहता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जिनके कारण व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। जैसे थायराइड से संबंधित बीमारियां, विटामिन डी की कमी और पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आदि। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण भी व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच सकता है। हालांकि अवसाद ग्रस्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में एकाकी रहना पसंद करता है।

लक्षण

कई ऐसे लक्षण हैं, जिनके आधार पर डिप्रेशन की मनोदशा का पता लगाया जा सकता है। जैसे...

उदासी या एकाकीपन

अगर व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद से ग्रस्त है, तो उसका किसी काम या विषय में मन नहीं लगता। हालांकि सामान्य उदासी अवसादग्रस्त उदासी से बिल्कुल भिन्न है। अवसादग्रस्त व्यक्ति की विभिन्न वस्तुओं या विषयों से रुचि खत्म हो जाती है, उसे खुशी या गम का अहसास नहीं होता। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता है।

नकारात्मक रवैया: किसी भी तरह की सकारात्मक सोच पर ये लोग ध्यान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति पर नकारात्मक सोच हावी रहती है।

शारीरिक अस्थिरता

अगर व्यक्ति अवसादग्रस्त है, तो उसे या तो अत्यधिक नींद आती है या फिर नींद कम आती है। कई बार आधी रात को ही नींद खुल जाती है। अवसादग्रस्त व्यक्ति को भूख कम लगती है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अवसाद आनुवांशिक कारणों से भी संभव है। अवसाद किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। अवसाद के भी विभिन्न स्तर हैं, जो इस प्रकार हैं- मेजर, क्रॉनिक, मैनिएक और अन्य प्रकार के अवसाद।

मेजर डिप्रेशन

एक गंभीर समस्या डिप्रेशन का सबसे सामान्य रूप है- मेजर डिप्रेशन।

इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं...

- पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक दुख, हताशा, ऊर्जा की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस करता है।
- किसी काम में ध्यान न लगना। नींद और खाने की आदतों में परिवर्तन।
- शारीरिक दर्द और आत्महत्या जैसे विचारों का अहसास।

इलाज: मेजर डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कम से कम दो हफ्ते से ज्यादा समय तक अगर उपर्युक्त लक्षणों से ग्रस्त हैं, तो उसके परिजनों को मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मेजर डिप्रेशन की चपेट में आने वाले 80 से 90 प्रतिशत व्यक्ति उचित इलाज से ठीक हो जाते हैं। इलाज के अंतर्गत दवाएं और मरीज के साथ ही उसके परिजनों की काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (मरीज के सोचने के ढंग को बदलने के लिए प्रेरित करना) भी दी जाती है।

बाइपोलर डिसऑर्डर

बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनिएक डिप्रेशन भी कहा जाता है, जो मानसिक चंचलता और मानसिक दिक्कतों का कारण बनता है। जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, तब वह दुखी या हताश महसूस करता है और किसी भी क्रियाकलाप के प्रति दिलचस्पी खो देता है, लेकिन जब उसका मूड दूसरी दिशा में शिफ्ट होता है, तब वह ऊर्जा से भरपूर और उल्लासमय नजर आता है। मूड का इस तरह बदलना जीवन में कई बार हो सकता है। कुछ लोगों में यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है।

इलाज: विशेषज्ञ की सलाह पर ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। ज्यादातर मामलों में बाइपोलर डिसऑर्डर को दवाओं और काउंसलिंग के जरिएनियंत्रित किया जा सकता है।

डिस्थाइमिया या क्रॉनिक डिप्रेशन

डिप्रेशन का यह सामान्य रूप मेजर डिप्रेशन से कम गंभीर होता है,लेकिन इसमें भी खतरा रहता है। डिस्थाइमिया इस प्रकार का डिप्रेशन होता है, जिसमें लंबे समय तक पीड़ित व्यक्ति की मानसिकस्थिति खराब रहती है। यह स्थिति एक साल या इससे भी ज्यादा समय के लिए हो सकती है।

उपचार

क्रॉनिक डिप्रेशन में दवाओं के साथ साइकोथेरेपी भी कारगर होती है। जो व्यक्ति डिस्थाइमिया की चपेट में होता है, उसे मेजर डिप्रेशन होने का खतरा रहता है।

सावधानियां बरतें

- डिप्रेशन पीड़ितों को उनके स्वभाव के लिए दोषी न ठहराएं।
- यह अपेक्षा न करें कि रोगी एकदम से ठीक हो जाएगा, क्योंकि इलाज की प्रक्रिया में वक्त लगता है।
- पीड़ितों को पारिवारिक व सामाजिक वार्तालाप में शामिल होने से न रोकें।
- उन्हें अकेला न छोड़ें।

शुरू कर सकते हैं खुद का कारोबार

पर्सलन स्टाइलिस्ट में बेहतर भविष्य खोज सकते हैं युवा

आजकल के युवा स्टाइल के मामले में किसी से भी कम नहीं वो अपनी लुक को बदलने के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेते हैं, जिन्हें पर्सनल स्टाइलिस्ट कहा जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी अपने कॅरियर को लेकर काफी जागरूक है। वो अपने कॅरियर का चुनाव बड़े ही सोच समझकर कर करते हैं। आप पर्सनल स्टाइलिस्ट बनने में भी अपने कॅरियर की शुरुआत कर सकते हैं। पर्सनल स्टाइलिस्ट का काम होता है लोगों का मेकओवर करना और लोगों के ड्रेसिंग सेंस को भी बढ़ाना।

फैशन जगत से रहें अपडेट

हर कॅरियर की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। पर्सनल स्टाइलिस्ट बनने के लिए आपको लोगों के मूड, फैशन के बदलते ट्रेंड , ड्रेसिंग सेंस के बारे में, इसके लिए आपको हर दिन की फैशन जगत की अपडेट रखनी होगी।

स्टडी सेंटर्स...

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
- पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन, दिल्ली

योग्यता...

इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिए ज्यादा शिक्षा की तो नहीं बल्कि आपके पास डिग्री होनी जरूरी है और इस क्षेत्र में काम करने के लिए आप फैशन डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आप चाहें तो खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसके अलावा आप फैशन, एंटरटेनमेंट, डिजाइनिंग वाले क्षेत्र में भी नौकरी पा सकते हैं।

गाड़ी के यूजर मैन्यूअल पर ध्यान दें...

गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि गाड़ी को अच्छी स्थिति में रखना। हम अक्सर कारों का इस्तेमाल लगभग हर दूसरे कामो में करते हैं लेकिन कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते कि कारों की देखभाल भी बड़े ही अच्छे और प्यार से करनी चाहिए। गाड़ी की अच्छी देखभाल करने का एक सबसे आसन और सरल उपाय है यूजर मैन्यूअल। आपकी गाड़ी से सम्बंधित हर छोटी बड़ी बातें इस यूजर मैन्यूअल में रहती हैं। हम ज्यादातर यूजर मैन्यूअल पढ़ते भी नहीं ढंग से, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि कितनी काम की जानकारियां इस यूजर मैन्यूअल से हमें मिल सकती हैं। तो अगर आप खुद गाड़ी की देखभाल करना चाहते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए गाड़ी को गैराज में नहीं ले जाना चाहते तो अपने गाड़ी के यूजर मैन्यूअल पर भी थोड़ा ध्यान दें।

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की जांच

गाड़ी को स्थिर कर खड़ा करें एक स्तर पर, फिर पार्किंग ब्रेक लगाएं और इंजन शुरू करें।अपने ट्रांसमिशन शिफ्टर को पोजिशन(पार्किंग) में रखें। इंजन को वैसे ही रहने दें। ट्रांसमिशन डीप स्टिक निकले। डीप स्टिक को एक साफ कपड़े से या फिर टिशू पेपर से पोछ लें, इसके बाद फिर डीप स्टिक को वापस जगह पे डाल दें। डालने के बाद फिर से निकालें और फ्लूअड लेवल चेक कर लें। अगर इंजन बंद है तो ये कोल्ड मार्क तक रहेगा। अगर गाड़ी चली है और गर्म है तो हॉट मार्क पर रहेगा। फ्लूअड कोलोर का भी ध्यान रखें।अगर ज्यादा गंदा है और खराब गंध आ रही है तो ट्रांसमिशन सही काम नहीं कर रहा है। इसे साफ और पारदर्शी रहना चाहिए। आप अपने गाड़ी की मैन्यूअल देख लें की इसे कब बदलने की जरूरत है। गाड़ी को कोई समतल जगह खड़े करें, इंजन बंद कर दें, थोड़ी देर रूकें कि इंजन आयल अपने स्तर पर आ जाए। इंजन की डीप स्टिक निकालें। इसे अच्छी तरह किसी सूखे कपड़े या फिर टिशू पेपर से पोछ के फिर वापस जगह पर डाल दें। अब इस डीप स्टिक को फिर से निकालें और इंजन आयल लेवल चेक करें। आमतौर पे ये फुल मार्क तक रहेगा, लेकिन ये अगर फुल मार्क के कुछ ज्यादा ही नीचे है तो फिर आपको इंजन आयल बदलने की जरूरत है। यह भी देख लें अगर इंजन आयल में ज्यादा कालापन आ गया है या फिर ज्यादा गन्दा हो गया है तो इसे तुरंत बदल दें।

इंजन कूलन्ट की जांच

इंजन कूलन्ट के कम होने पर इंजन-ओवरहीट हो जाता जो की इंजन की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इंजन कूलन्ट का स्तर लो और फुल मार्क के बीच में रहना चाहिए। अगर आप बार बार कूलन्ट डाल रहे हैं फिर भी टैंक में सही मात्र में कूलन्ट नहीं है तो हो सकता है कि कूलन्ट लीक हो रही हो।

रेसिपी

अचारी पनीर

सामग्री

अचारी मॅरीनेड के लिए, 1/2 कप चक्का दही, 1 टेबल-स्पून हरीमिर्च का आचार, 1 टी-स्पून कटा लहसुन, 1 टी-स्पून सौंफ, 1/4 टी-स्पून मेथी दाना, 1/4 टी-स्पून कलौंजी, 1 टी-स्पून जीरा, 1/4 टी-स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल-स्पून राई का तेल, नमक स्वादानुसार

विधि

अचारी मॅरीनेड के लिए: दही, हरीमिर्च का आचार और लहसुन को मिक्सर में डालकर मुलायम पेस्ट बना लीजिए। एक बाउल में निकालकर एक तरफ रख दीजिए। शेष बची सारी सामग्री को ब्लैंडर में डालकर दरदरा पीस लीजिए। दरदरे पिसे पाउडर और दही के पेस्ट को एक बाउल में डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। एक तरफ रख दीजिए। अब कड़ाही में तेल डालकर उसमें सारे सामग्री को मिला लें थोड़ी देर पकाने के बाद उसमें पनीर के टुकड़ों को डाल दीजिए और फिर थोड़ी देर पकने दें उसके बाद उसे किसी बाउल में निकाल लीजिए, हो गया आपका अचारी पनीर तैयार। आप इसे पराठा, पूरी या फिर चावल के साथ भी खाने का मजा लें सकते हैं।

खीरे का चीला

सामग्री

250 ग्राम बेसन, 200 ग्राम खीरा, 150 ग्राम बड़े टमाटर, 1 टे.स्पून हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 15-20 करी पत्ता, स्वादानुसार नमक, एक चौथाई टी स्पून लाल मिर्च, तलने के लिए तेल।

विधि

खीरा छीलकर कस लें, हल्के हाथ से दबा थोड़ा पानी निकाल लें। टमाटर को खौलते पानी में दो-तीन मिनट रखकर निकालकर छिलका उतारकर रस निकाल लें व छान लें। धनिया, अदरक व हरी मिर्च मिलाकर पीस लें। करी पत्ता महीन काट लें। बेसन मे तेल छोड़ बाकी सारा सामान मिला चीले जैसा घोल बना लें। तवे में तेल गर्मकर एक बड़ी चम्मच में घोल लेकर तीन-चार जगह छोड़ दें। लाल हो जाने पर चिमटे से पलट कर दूसरी तरफ भी लाल कर निकाल लें एवं अच्छी तरह तेल झारकर गरमागरम परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**